



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/फाल्गुन 14, 1940

No. 68]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/ PHALGUNA 14, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2019

मामला सं. एस एस आर 14/2018

विषय : यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये एसिटोन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा में जांच परिणाम।

फा. सं. 7/26/2018—डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 उसके पश्चात (इसके रूप में भी संदर्भित) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया हो, (इसके पश्चात पाटनरोधी अथवा नियमावली के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में, महानिदेशक (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) ने यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके पश्चात् संबद्ध देशों के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "एसिटोन" (इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू की थी।

क. पृष्ठभूमि

- जबकि, चीनी ताइपेई, यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा 7 सितंबर, 2006 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 25 अप्रैल, 2007 के प्रारंभिक जांच परिणाम के माध्यम से अंतिम शुल्क, जिसे दिनांक 19 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 77/2007 – सीमा शुल्क द्वारा लगाया गया था, को लगाये जाने की सिफारिश की। दिनांक 4 जनवरी, 2008 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/4/2006 – डी जी ए डी ने चीनी ताइपेई,

यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जिसे दिनांक 11 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 33/2008 – सीमा शुल्क के माध्यम से लागू किया गया था।

2. जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ताइवान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध मध्यावधि समीक्षा जांच की और दिनांक 10 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं से पाटनरोधी शुल्क वापस लिये जाने की सिफारिश की, जिसे दिनांक 29 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 29/2012 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लागू किया गया था।
3. जबकि, पांच वर्षों तक लागू शुल्कों के समाप्त होने पर प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा शुरू की और दिनांक 13 दिसंबर, 2013 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/1/2012 – डी जी ए डी के माध्यम से यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार, सीमा शुल्क प्राधिकारी ने दिनांक 11 मार्च, 2014 की एक अधिसूचना संख्या 10/2014 सीमा शुल्क (ए डी डी) शुल्क को लगाये जाने के लिए जारी किया।
4. जबकि, इस अधिनियम की धारा 9क (5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में निरस्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार से लगाये जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या इस शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किये गये एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है।
5. जबकि, इस अधिनियम की धारा 9क (5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में निरस्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार से लगाये जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या इस शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किये गये एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है।
6. जबकि, एस आई ग्रुप इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमि. (इसके पश्चात् याचिकाकर्ता के रूप में भी संदर्भित) ने मैसर्स हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल) से समर्थन पत्र के साथ साथ पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध करते हुए और यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के विरुद्ध शुल्कों को जारी रखने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। यह अनुरोध इन आधारों पर किया गया था कि इस उपाय के समाप्त होने के फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना थी।
7. घरेलू उद्योग की ओर से दायर किये गये पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी ने यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को सतत् रूप से लगाये जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 7/26/2018 – डी जी ए डी के माध्यम से दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
8. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व जांचों के सभी पहलु शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

9. इसमें नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :

- i. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत महानिदेशक को यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के लिए अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग की ओर से याचिकाकर्ताओं से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।
- ii. एक विधिवत प्रमाणित आवेदन के प्राप्त होने पर, प्राधिकारी ने दिनांक 6 जुलाई, 2018 को जांच शुरूआत अधिसूचना संख्या 7/26/2018 – डी जी ए डी जारी किया और जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया और जिसके माध्यम से यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू की गई।
- iii. नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावास को जांच शुरूआत अधिसूचना और इस याचिका का अगोपनीय पाठ की प्रति के साथ साथ नियम 6(2) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांचों को आरंभ किये जाने के बारे में सूचना दी गई थी।
- iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों (जिनके नाम व पते याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को इस अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित की और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) और नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अवसर प्रदान किया।
 - क. स्टोनमिल ए बी, स्वीडन
 - ख. बी ओ सी साईंस, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - ग. ई एम सी ओ केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - घ. आई सी सी केमिकल कोरपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - ङ. बी के एम रिसोर्सिस इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - च. माइल्स केमिकल कंपनी इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - छ. हबबर्ड-हाल, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - ज. इकोलिक, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - झ. सेडलर केमिकल कं., इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - ञ. ए डी डी रेसिन्स एंड केमिकल्स (पीटीवाई) लिमि., दक्षिण अफ्रीका
 - ट. प्रोटी केमिकल्स, दक्षिण अफ्रीका
 - ठ. सासोल सोलवेंट्स, दक्षिण अफ्रीका
 - ड. एमका प्रॉडक्ट्स (पीटीवाई) लिमि., दक्षिण अफ्रीका
 - ढ. रोलफेस होल्लिंग्स लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका
 - ण. योग ट्रेडिंग पीटीई. लिमि., सिंगापुर
 - त. विगोर सफेरे पीटीई. लिमि. सिंगापुर
 - थ. एडवांस पिन्नाकले टेक्नोलॉजी, सिंगापुर
 - द. पोलीमेर टेक्नोलॉजी पीटीई. लिमि., सिंगापुर
 - ध. हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमि., सिंगापुर
- v. यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सिंगापुर के निम्नलिखित उत्पादक और निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
 - क. मित्स्यू एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई. लिमि.
 - ख. मित्स्यू फेनोल्स सिंगापुर पीटीई. लिमि.

vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं (जिनके नाम व पते आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को इस अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित की और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी :

- क. मैसर्स सी. जे. शाह एंड कंपनी
- ख. मैसर्स पी सी एल ऑयल एंड इंडस्ट्रीज
- ग. मैसर्स कांतिकाल मनिलाल एंड कं. प्रा. लिमि.
- घ. मैसर्स सोनकमल इंटरप्राइजेज
- ङ. मैसर्स खेतान ब्रोदर्स
- च. मैसर्स शुभम डाइस एंड केमिकल्स लिमिटेड
- छ. मैसर्स एक्रॉन इंटरप्राइजेज
- ज. मैसर्स नेकनावारे केमिकल्स लिमिटेड
- झ. मैसर्स पारस डाइस एंड केमिकल्स
- ञ. मैसर्स टोरेंट फार्मासिस्टिकल्स लिमिटेड
- ट. मैसर्स यूनाइटेड फोस्फेरस लिमि.
- ठ. मैसर्स रेसिंस एंड प्लास्टिक लिमि.
- ड. मैसर्स कैलाश पालीमर्स
- ढ. मैसर्स सेन्ट्रम मेटालिक्स प्रा. लिमि.
- ण. मैसर्स वन्दर लेमिनेट्स प्रा. लिमि.
- त. मैसर्स मेघदेव इंटरप्राइजेज
- थ. मैसर्स सतगुरु इंटरनेशनल
- द. मैसर्स हाई पोलिमेर लेव्स लिमि.
- ध. मैसर्स रेनबो कलर्स एंड केमिकल्स
- न. मैसर्स हारेश कुमार एंड कं.
- प. मैसर्स ब्लेच मार्केटिंग प्रा. लिमि.
- फ. मैसर्स करमन इंटरनेशनल (प्रा.) लिमि.
- ब. मैसर्स कृष्णा एंटीओक्सीडेंट प्रा. लिमि.
- भ. मैसर्स एन जी पी इंडस्ट्रीज लिमि.
- म. मैसर्स फार्मसन फार्मासिटिकल गुजराज लिमि.
- य. मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमि.
- र. मैसर्स सिंह प्लास्टिसीजर्स एंड रेसिंस (I) प्रा.
- ल. मैसर्स नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लिमि.
- व. कुंदन राइस मिल्स लिमि.

vii. जबकि, किसी भी आयातक/ उपभोक्ता ने भेजी गई आयातक की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

- viii. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 (12 महीने) है। हालांकि, क्षति के विश्लेषण की अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि शामिल है।
- ix. जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए लेन देन वार आयात आंकड़े वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से लिये गये थे। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों और को-आपरेटिव उत्पादक निर्यातक के आंकड़ों पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए विश्वास किया है।
- x. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिये खुली रखी गई सार्वजनिक याचिका के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- xi. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत तय करने के लिए इस नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की यथासंभव जांच की है।
- xii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 18 सितंबर, 2018 को आयोजित मौखिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी अवसर उपलब्ध कराये। इन पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों को लिखित अनुरोध और उसके पश्चात् प्रतिउत्तर के रूप में अनुरोधों को प्रस्तुत करें।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों, जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच में साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित और उसे संगत माना गया, इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xiv. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में अपने आप को संतुष्ट किया जो इस अंतिम जांच परिणाम का उस सीमा तक आधार बनता है और उसने संगत और आवश्यक मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दिये गये आंकड़ों/ दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- xv. एक प्रकटन विवरण दिनांक 22.02.2019 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य निहित थे और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 01.03.2019 तक समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- xvii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच को सार्थक रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उसे इस अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किया है।
- xviii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से मानी गई सूचना को द्योतक है।
- xix. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमरीकी डालर = 65.33 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) और समान वस्तु का कार्यक्षेत्र

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

10. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

- क. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व की जांचों में था अर्थात् एसिटोन।
- ख. विचाराधीन उत्पाद एक ऑर्गेनिक रसायन है जिसे डिमेथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है और जिसका उपयोग भारी मात्रा में दवा, कृषि से संबंधित रसायनिक पदार्थों, रंजन पदार्थों, कुछ विस्फोटकों और डाउनस्ट्रीम रसायनिक पदार्थों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
- ग. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जिसे पूर्व में आयोजित जांच में परिभाषित किया गया है, कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस अवधि के दौरान नहीं हुआ है। इस कारण से घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व की जांचों का संदर्भ लेता है और उस पर विश्वास करता है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

11. विचाराधीन अथवा समान वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किये गये थे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद एसिटोन है। एसिटोन ऑर्गेनिक रसायन है जिसे डिमेथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है।

13. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है अतः प्राधिकारी इस तथ्य को मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही रहता है जो मूल और परिणामी समीक्षा जांचों में है। पूर्व की जांचों में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे दिये गये अनुसार है :

“6. विचाराधीन उत्पाद ‘एसिटोन’ है, एसिटोन ऑर्गेनिक रसायन है जिसे डिमेथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है और जिसका उपयोग भारी मात्रा में दवाओं, कृषि से संबंधित रासायनिक पदार्थों, रंजन पदार्थों, कुछ विस्फोटकों और डाउनस्ट्रीम रसायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। एसिटोन का वर्गीकरण उप-शीर्षक 29141100 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत किया गया है।

7. यह एक मूलभूत ऑर्गेनिक रसायन पदार्थ है जिसका उत्पादन एकल ग्रेड में किया जाता है। यह एक अनुकूल ईंधन जैसे गंध के साथ बिना रंग वाला तरल पदार्थ है। इसका उपयोग या तो द्रावक अथवा एक मध्यवर्ती के रूप में अनेक ऑर्गेनिक मिलावटों में किया जाता है। इसका उपयोग भारी मात्रा में दवाओं, कृषि से संबंधित रासायनिक पदार्थों, रंजन पदार्थों, कुछ विस्फोटकों और डाउनस्ट्रीम रसायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। एसिटोन का विशेष रूप से उपयोग आइसोफोरोन, डाइसिटोन, एल्कोहल, मिथाइल मेथाक्राइलेट और बिसफेनोल ए के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग कुछ रबड़ रासायनिक पदार्थों अथवा ऑक्सी एसिथालिन सेल्यूलोस एसिडेट के निर्माण में किया जाता है।”

14. रिकार्ड पर दी गई सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद की तुलना इन वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद, विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में विचाराधीन उत्पाद से की जा सकती है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

15. प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपर्युक्त पैराओं में यथाउल्लिखित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन किये जा रहे संबद्ध वस्तुओं को प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय से संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं का समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार**घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

16. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की पात्रता और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये :

- क. यह आवेदन मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल) के समर्थन के साथ साथ मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमि. द्वारा दायर किया गया।
- ख. दीपक फेनोलिक्स ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है जबकि एस आई ग्रुप ने कुछ मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है जो संबद्ध देशों से कुल आयातों का मात्र 1 प्रतिशत और मांग का 1 प्रतिशत है। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया है और इस कारण से वह घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए पात्र है।
- ग. याचिकाकर्ता संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक और भारत में आयातकों से या तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित नहीं है।
- घ. याचिकाकर्ता भारतीय उत्पादन का 'एक बड़ा हिस्सा' है। याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को दायर करने के लिए आधार की आवश्यकता को पूरा करता है और वह पाटनरोधी नियमावली के आशय से 'घरेलू उद्योग' होता है। यह कानूनी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है कि इस आधार को निर्णायक समीक्षाओं के चरण में जांच किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- ङ. जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुपालन में, जांच की अवधि के लिए अद्यतित सूचना घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में एच ओ सी एल को मानते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी।
- च. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा नहीं किया है कि दीपक फेनोलिक्स एक मौजूदा स्थापित घरेलू उद्योग है। दीपक फेनोलिक्स केवल एक समर्थक के रूप में इस आवेदन का हिस्सा है।
- छ. दीपक फेनोलिक क्षति की संभवना के लिए प्रत्यक्ष रूप से संगत है जिसमें 1400 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है और भारत में भारी मांग को पूरा करते हुए संबद्ध वस्तुओं का व्यापारिक उत्पादन शुरू करेगा।
- ज. यह आवेदक घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है। इस कारण से आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यथापरिभाषित पात्र घरेलू उद्योग है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

17. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की पात्रता और इसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- क. दीपक फेनोलिक्स को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन नहीं शुरू किया है।
- ख. एस आई ग्रुप ने पूरी अवधि के दौरान एसिटोन का आयात किया है उसके लिए कारणों को न तो बताया गया है और न ही उनका विश्लेषण किया गया है। इस कारण से अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत एस आई ग्रुप द्वारा किये गये आयातों का प्राधिकारी द्वारा फिर से आकलन किया जाना चाहिए।
- ग. दीपक फेनोलिक्स ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, वास्तव में इस संयंत्र को अभी चालू किया जाना है। इस कारण से अनुच्छेद 3 में संशोधन के द्वारा यथाप्रस्तावित मानदंड याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होते हैं – (1) क्षमता का उपयोग, (2) यह विलंब उचित व्यापारिक उत्पादन का आरंभ है, (3) घरेलू उत्पादन की तुलना घरेलू बाजार से की गई है।
- घ. एच ओ सी एल निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार निर्धारण में शामिल किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है अथवा नहीं। तर्क के साथ उसके संबद्ध में स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. यह याचिका मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल) से समर्थन पत्र के साथ साथ मैसर्स एस आई ग्रुप इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स दीपक फेनोलिक लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। बाद में,

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को मैसर्स एच ओ सी एल के लिए संगत आंकड़े प्रस्तुत करने का निदेश दिया। दिये गये निदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा संगत आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे।

19. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स दीपक फेनोलिक्स ने अभी तक उत्पादन आरंभ नहीं किया है और एच ओ सी एल ने पूरे वर्ष के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्माण नहीं किया है। समर्थकों के साथ साथ एस आई ग्रुप कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह प्रमाणित किया है कि उनका भारत में किसी निर्यातक अथवा आयातक के संबंध नहीं है।
20. एस आई ग्रुप ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। यह आयात शुल्क मुक्त अधिकरण योजना के अंतर्गत किये गये थे। जांच के बाद यह नोट किया गया था कि उत्पादक द्वारा इन वस्तुओं के उत्पादन अथवा इन वस्तुओं के कुल आयातों की तुलना में आयात बहुत कम मात्रा में किया गया है।
21. उपर्युक्त को देखते हुए और उचित जांच किये जाने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक संबद्ध वस्तुओं के लिए आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होता है।

ङ गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

22. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये :

- क. उत्तर देने वाले निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता के दावे का सहारा लिया है जिसमें याचिकाकर्ताओं को उनकी टिप्पणियां देने से पूर्ण रूप से रोक दिया है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किये गये क्षति संबंधी विवरण आवश्यक रूप से या तो वास्तविक आधार पर हैं अथवा सूचीबद्ध आधार पर। घरेलू उद्योग द्वारा और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा क्षति संबंधी मानदंडों का अगोपनीय पाठ की तुलना उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता की सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शायेगा।
- ग. घरेलू उद्योग ने क्षति संबंधी मानदंडों की प्रवृत्ति को दर्शाते हुए प्रत्येक मानदंड के सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, निर्यातकों ने सूचीबद्ध आंकड़ों की सीमा उपलब्ध कराने का विकल्प लिया है। उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अगोपनीय पाठ पुनः एक प्रयास है जो याचिकाकर्ता का अपने हित की रक्षा करने के अधिकार को कम करता है।
- घ. निर्यातक ने उत्पाद की सूची, वितरण का माध्यम, उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन का प्रवाह तालिका, कच्चे माल का नाम, भारत में किये गये निर्यातों से संबंधित सूचना, कंपनी के इन मालों की बिक्री, बिक्री के लिये कीमत ढांचा, संस्थापित क्षमता को दर्शाते हुए विवरण, उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना, सहायक कंपनी से संबंधित सूचना, तीसरे देशों में निर्यात के संबंध में सूचना आदि जैसी सूचनाओं का दावा किया है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय पाठ पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस प्रकार की सभी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया है कि वे इस निमयावली के अंतर्गत प्रकट करने के लिए बाध्य हैं। उस सूचना जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है को भी अगोपनीय पाठ में प्रकट नहीं किया गया है।
- ङ. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 के हाल के व्यापार नोटिस संख्या 10/2018 के अनुसार इस सूचना का संशोधित अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

23. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

- क. सामान्य मूल्य को तय करने के लिए विभिन्न लागतों हेतु उपयोग किये गये साक्ष्य का गोपनीयता के रूप में दावा किया गया है। यह दावा प्रकृति से एकतरफा है और यह प्रत्यक्ष रूप से निर्यातकों के हित को नुकसान पहुंचाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किये गये अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोधों की जांच की गई और उसका समाधान तदनुसार किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने

गोपनीयता संबंधी दावे को जहां भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, कार्य निष्पादन संबंधी मानदंडों और क्षति से संबंधित मानदंडों के बारे में सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना प्रथा के अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

च. विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

25. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

- क. ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की जांच के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातों को शामिल किया है जबकि यह इस तथ्य को मान रहा हो कि ये आयात निर्यात उत्पादन के लिए हुए हैं। क्षति के निर्धारण से अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातों को बाहर किये जाने का न तो कोई कानूनी और न ही कोई तथ्यात्मक आधार है।
- ख. प्राधिकारी ने अन्य मामलों में भी यह माना है कि यह तथ्य कि ये आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किये गये थे, का यह आशय नहीं होता है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

26. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

- क. बाजार की सूचना के अनुसार, आयातों का एक बड़ा हिस्सा अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान किया गया है। चूंकि, इन योजनाओं को निर्यात उन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है और व्यापार उपचारात्मक शुल्कों को लगाये जाने से छूट दी जाती है। अतः उन्हें क्षति के विश्लेषण के लिए आयात मात्राओं से बाहर किया जाना चाहिए।
- ख. सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रथा और नीतियां मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप होनी चाहिए। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार के पाटनरोधी शुल्क से छूट प्रदान की जाती है जबकि इन शुल्कों को इस प्रकार के आयातों को शामिल करते हुए आयात की मात्राओं का उपयोग करते हुए अब लगाया जा रहा है। थाई एक्रलिक फाइबर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेस्टेट के अनुसार अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात भारतीय बाजार में नहीं होता है और यह भारतीय विक्री से प्रतिस्पर्धा नहीं करती है।
- ग. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात दूसरी निर्णायक समीक्षा के कार्यक्षेत्र से परे है। इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या शुल्कों को समाप्त किये जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है, इन आयातों जिन पर इन शुल्कों का कभी भी प्रवाह नहीं पड़ा है, की जांच करना तार्किक नहीं है। केवल वे आयात जिन पर इस शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी, की जांच की जानी चाहिए। अग्रिम लाइसेंस आयात इस तर्क पर विचार किये बिना प्रभाविक नहीं होगी कि शुल्क है अथवा नहीं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. विरोधी पक्षकारों द्वारा किये गये विशिष्ट अनुरोधों और संगत माने गये अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून में स्पष्ट रूप से इस पर विचार किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क आगे समय समय पर बढ़ाया जा सकता है, यदि ऐसा पाया गया हो कि पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में फिर से उत्पन्न होने की संभावना

है। प्राधिकारी इन कानूनों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

- ख. यह शर्त की आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया गया था, को उन आयातों से बाहर किया जाना चाहिए कि जांच की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किये गये आयातों/ निर्यातों को ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उसके कारण घरेलू उद्योग अथवा घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अग्रिम लाइसेंस/ अनुमोदन धारक के पास विकल्प है कि या तो वे शुल्क मुक्त आधार पर इनपुट्स का आयात करें अथवा अग्रिम रिलीज आर्डर के तंत्र का उपयोग करते हुए स्वदेशी स्रोतों से उसे प्राप्त करें। क्षति विश्लेषण का उद्देश्य घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करना और उसे अपने कब्जे में लेना है। इस कारण से यह उचित नहीं होगा कि क्षति संबंधी विश्लेषण से शुल्क मुक्त आयातों को बाहर किया जाए। इसके अलावा, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात उस कीमत के लिए एक बैच मार्क है जिस पर इन वस्तुओं का आयात उपभोक्ता द्वारा करें और शुल्कों का भुगतान किये बिना किया जा सकता है। यह उचित नहीं होगा कि इस तथ्य पर विचार किया जाये कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किये गये आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है। वास्तव में निर्यातक और आयातक को इस तथ्य की चिंता नहीं करनी चाहिए कि यदि उनके दावे यह हैं कि आयात शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत ही होता है क्योंकि वैसी स्थिति में शुल्क को लगाये जाने से उन पर बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की पद्धति और निर्धारण

28. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

29. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

- क. उत्पादकों की वास्तविक लेन देन कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसको देखते हुए, संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्यों का निर्धारण उत्पादन की लागत के आकलन के आधार पर किया गया है।
- ख. निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन संबंधी खर्च और अंतर्देशीय भाड़े का सामायोजन किया जाना चाहिए।
- ग. पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है।
- घ. पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का सतत् पाटन हो रहा है।

- ड. चूंकि उत्तर देने वाले निर्यातक/ उत्पादक ने उचित समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की है अतः प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उत्तर देने वाले पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली का अपूर्ण उत्तर को अस्वीकार करें और नियम 6 (8) और जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के अनुपालन में उन्हें असहयोगी के रूप में माने।
- च. न तो उत्तर देने वाले निर्यातक/ उत्पादक और न ही उनके प्रतिनिधि इन जांचों के लिए नये हैं और इस कारण से वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें निर्णायक समीक्षा के प्रश्नावली के भाग 2 की जानकारी नहीं थी। यह जानबूझकर भूल किये जाने का एक स्पष्ट मामला है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

30. प्राधिकारी को इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए निर्यातकों के उत्तरों का आकलन करना चाहिए कि क्या पाटन थोड़ा भी जारी रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. जांच शुरूआत के चरण में प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आगे की कार्यवाही आरंभ की। जांच आरंभ करने पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/ निर्यातकों को जांच शुरूआत की सूचना का उत्तर देने और उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। सिंगापुर के निर्यातकों अर्थात् मित्सू एंड कं. (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमि. और मित्सू फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमि. से ही उत्तर प्राप्त हुए थे।

सामान्य मूल्य

सिंगापुर : मैसर्स मित्सू फेनोल सिंगापुर पीटीई. लिमि. एंड मैसर्स मित्सू एंड कं. (एशिया प्रशांत) पीटीई. लिमि.

32. उत्तर देने वाले उत्पादक ने अपने घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत किया है, इस प्रकार से उपलब्ध कराई गई सूचना पर व्यापार जांच और पर्याप्तता जांच की सामान्य प्रक्रिया करने के बाद संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विश्वास किया गया है। उन्होंने इन वस्तुओं को अपनी संबंधित कंपनी अर्थात् मैसर्स मित्सू एंड कं. (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमि. के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बेचा है। भंडारण की लागत, बैंक प्रभार, ऋण लागतों और अन्य सामायोजनों के संबंध में दावा किये गये अनुसार इन समायोजनों को कारखानागत सामान्य मूल्य तय करने के लिए सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया था। कारखानागत लागत का निर्धारण कंपनी की लेखा बुक के आधार पर किया गया था और उसकी तुलना घरेलू बाजार में बेची गई वस्तुओं की कारखानागत बिक्री कीमत के साथ की गई थी। यह पाया गया था कि 100 प्रतिशत बिक्री लाभप्रद है। इस प्रकार से निर्धारण किये गये सामान्य मूल्य वही है जिसका उल्लेख नीचे दिये गये पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य संबद्ध देशों से कोई अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य तय करने का प्रस्ताव करते हैं। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों और लाभों को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन की संगठित लागतों के आधार पर की जानी है। संरचित सामान्य मूल्य वही है जिसका उल्लेख नीचे दिये गये पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

सिंगापुर : मैसर्स मित्सू फेनोल सिंगापुर पीटीई. लिमि. एंड मैसर्स मित्सू एंड कं. (एशिया प्रशांत) पीटीई. लिमि.

34. मैसर्स मित्सू फेनोल सिंगापुर पीटीई. लिमि. ने अपने संबंधित निर्यातक मैसर्स मित्सू एंड कं. (एशिया प्रशांत) पीटीई. लिमि. के माध्यम से भारत में इन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। उन्होंने भारत में निर्यात से संबंधित पूर्ण सूचना प्रस्तुत की है। इन समायोजनों का दावा भंडारण लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के आधार पर किया गया है, उसे सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया था। इस प्रकार से निर्धारित प्रस्तावित निवल निर्यात कीमत वही है जिसका उल्लेख नीचे दिये गये पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका

35. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने वर्तमान मामले में भाग नहीं लिया है। इसको देखते हुए, प्राधिकारी उन सभी निर्यातकों जिन्होंने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, के लिए डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों से निवल निर्यात कीमत (लागू समायोजनों के साथ) संरचित करने का प्रस्ताव करते हैं।

झ. पाटन मार्जिन

36. ऊपर में दिये गये सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किये जाने का प्रस्ताव है :

विवरण	एन वी/ सी एन वी	एन ई पी	पाटन मार्जिन		
	यू एस डी/ मी. ट.	यू एस डी/ मी. ट.	यू एस डी/ मी. ट.	%	रेंज
मित्सुई फेनोल्स सिंगापुर पीटीई. लिमि. एंड	***	***	***	***	5 - 15
ई यू	***	612.03	***	***	35-45
दक्षिण अफ्रीका	***	601.75	***	***	35-45
यू एस ए	***	671.59	***	***	35-45

37. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम स्तरों से ऊपर है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण**घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

38. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया है :

- क. विचाराधीन उत्पाद के लिये मांग में क्षति के अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह आधार वर्ष से जांच की अवधि में 17 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- ख. संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में कमी आई है। संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का लगभग 8 प्रतिशत था।
- ग. अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, हालांकि घरेलू उद्योग ने तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के बारे में एक अलग याचिका दायर की है।
- घ. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है।
- ङ. घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत के दबाव से नुकसान हो रहा है क्योंकि बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट से अधिक है।
- च. आयातों की पहुंच कीमत परिकलित क्षति रहित कीमत से बहुत कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने के बावजूद उचित बिक्री अथवा क्षति रहित कीमत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य हो गया है।
- छ. उत्पादन और क्षमता के उपयोग में 2015-16 में गिरावट आई और तब 2016-17 और जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री 2016-17 तक कम हुई, लेकिन जांच की अवधि में यह बढ़ गई।
- ज. घरेलू उद्योग की मांग और बाजार हिस्से में वृद्धि के बावजूद, लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा है और घरेलू उद्योग क्षति की पूरी अवधि के दौरान घाटे में है।

- झ. माल सूची में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।
- ज. घरेलू उद्योग को लाभप्रदता के संबंध में हानि उठानी पड़ी है। घरेलू उद्योग क्षति की पूरी अवधि के दौरान घाटे में रहा है और इसका घाटा जांच की अवधि में मामूली सुधार के साथ 2014-15 और 2016-17 में बढ़ा है।
- ट. नियोजित पूंजी पर लाभ की भी वही प्रवृत्ति रही है जबकि यह जांच की अवधि में मामूली सुधार के साथ क्षति की पूरी अवधि के दौरान ऋणात्मक रही है।
- ठ. तीसरे देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने उसके लिए एक अलग याचिका दायर की है क्योंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और नये देशों को जोड़ा नहीं जा सकता था।
- ड. उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है और इस कारण से यह क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- ढ. अन्य ज्ञात कारकों का विश्लेषण किया गया है और वे घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।
- ण. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद में प्रतिकूल कीमत प्रभाव और न कि प्रतिकूल मात्रा संबंधी प्रभावों का दावा कर रहा है।
- त. घरेलू उद्योग बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के लिए पाटित आयातों के अनुरूप अपनी कीमतों को रखने के लिए बाध्य है।
- थ. चूंकि एच ओ सी एल केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है अतः कंपनी की कई वृहत आर्थिक पहलुओं का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। इस कारण से वृहत आर्थिक मुद्दे जिन्हें एच ओ सी एल के बारे में उठाया जा रहा है, को कंपनी के कार्य प्रबंधन की ओर से अपर्याप्तता के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- द. याचिकाकर्ताओं ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जो यह दर्शाते हैं कि एच ओ सी एल का निम्नतम खपत कारक है और इस कारण से वह एक कार्यक्षम कंपनी नहीं है जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का प्रश्न है।
- ध. यह तथ्य कि आयात की कीमतों को कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं रखा गया है अपने आप में भेदभाव पूर्ण कीमत निर्धारण को सिद्ध करता है जिसका सहारा विदेशी उत्पादकों द्वारा लिया गया है।

विरोधी पक्षकारों का दृष्टिकोण

39. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :

- क. क्षति का विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के आधार के आकलन के पश्चात किया जाना है। मात्रा संबंधी क्षति ने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किये गये आयातों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।
- ख. जांच की अवधि की तुलना में आधार वर्ष के रूप में मात्रा के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है। आयातों में बहुत अधिक गिरावट आई है। उत्पादन और मांग/ खपत के संबंध में जांच की अवधि बनाम आधार वर्ष में किये गये आयातों में गिरावट आई है।
- ग. कथित कटौती के बावजूद याचिकाकर्ता का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा हो रहा है।
- घ. उन अवधियों में लाभों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है जब अपेक्षाकृत अधिक कटौती हुई थी। इस प्रकार से अन्य कारक याचिकाकर्ताओं के कार्य निष्पादन और न कि संबद्ध आयातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
- ड. कथित कटौती का प्रभाव याचिकाकर्ताओं के कीमत निर्धारण पर नहीं पड़ा है क्योंकि इन लागतों को कच्चे माल की कीमत निर्धारण के अनुरूप रखा गया है। इस कारण से कोई ह्रास/ न्यूनीकरण नहीं हुआ है।
- च. याचिका में यह माना गया है कि उत्पादन और बिक्री की मात्रा जैसे आर्थिक मानदंडों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है। इस कारण से आर्थिक मानदंडों पर कोई क्षति नहीं हुई है।
- छ. यदि सतत् पाटन को भी सिद्ध कर दिया जाये तब कोई सतत् क्षति नहीं हुई है और इस कारण से कारणात्मक संबंध टूट गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

40. प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किये गये क्षति संबंधी विश्लेषण अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

41. पाटनरोधी नियमावली का इसके अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए" घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।
42. इस नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान किसी समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन यह दर्शाता हो कि इसे क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किये जाने से घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से उत्पन्न होने की संभावना है।
43. इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबंधित देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही करते हैं। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध - II के अनुसार ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है जिसका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति और पाटन का आकार एवं मार्जिन।

I. मांग का आकलन

44. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को आवेदक की घरेलू बिक्री और कैप्टिव खपत और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलन की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	19,937	22,401	21,620	22,341
सहायक की बिक्री	मी. ट.	6,167	2,648	4,722	10,609
संबंधित देशों से आयात	मी. ट.	20,701	24,080	10,167	14,539
उन देशों से आयात जिन पर शुल्क लगता है	मी. ट.	104,082	94,173	56,869	42,257
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	1,989	20,096	68,801	89,811
कुल मांग	मी. ट.	152,876	163,399	162,180	179,556
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	106	117

45. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिये मांग में वर्ष 2016-17 को छोड़कर जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

II. पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

I. आयातों की मात्रा और आयातों का बाजार हिस्सा

46. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किये गये लेन देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
संबंधित देशों से आयात	मी. ट.	20,701	24,080	10,167	14,539
उन देशों से आयात जिन शुल्क लगता है	मी. ट.	104,082	94,173	56,869	42,257
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	1,989	20,096	68,801	89,811
कुल आयात	मी. ट.	126,772	138,350	135,838	146,606
निम्नलिखित की तुलना में संबंधित देशों से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	79.67	96.48	38.09	44.23
मांग	%	13.54	14.74	6.27	8.10

47. यह देखा गया है कि :

- क. संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है लेकिन पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख. भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में 2015-16 में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई।
- ग. कुल मांग की तुलना में आयातों ने वही प्रवृत्ति दर्शायी है जो उत्पादन की तुलना में आयातों में दर्शायी है।

III. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

48. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान किया गया है :

"कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव जिसका उल्लेख नियम 18 के उपनियम (2) में किया गया है, के संबंध में महानिदेशक इस तथ्य पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में होनी होती।"

49. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संबंध में महानिदेशक से यह अपेक्षित है कि वे कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत पर ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संबंध में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करें।

i. कीमत में कटौती

50. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की आयातों के कारण कीमतों में कटौती हो रही है, घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूटों एवं करों की निवल राशि के आधार पर घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत के बीच तुलना के लिए सूचना दी है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया कि थोक और ड्रम पैकिंग की कीमत अलग अलग है और दोनों के लिए पृथक् रूप से ब्यौरा दिया गया है। तदनुसार, सभी चार संबद्ध देशों के लिए घरेलू कीमतें और कटौती का मार्जिन नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

यूरोपीय संघ

विवरण	इकाई	पी ओ आई	थोक	पैक किया हुआ
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एन एस आर)	रु./ मी. ट.	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	50,956	50,917	53,579
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	5-15	5-15	10-20

सिंगापुर

विवरण	इकाई	पी ओ आई	थोक	पैक किया हुआ
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एन एस आर)	रु./ मी. ट.	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	50,803	50,765	64,640
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	5-15	5-15	0-10

दक्षिण अफ्रीका

विवरण	इकाई	पी ओ आई	थोक	पैक किया हुआ
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एन एस आर)	रु./ मी. ट.	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	51,612	49,589	67,859
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***
कीमत में कटौती		5-15	5-15	(ऋणात्मक)

संयुक्त राज्य अमेरिका

विवरण	इकाई	पी ओ आई	थोक	पैक किया हुआ
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एन एस आर)	रु./ मी. ट.	-	-	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	-	-	56,864
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	-	-	***
कीमत में कटौती	%	-	-	***
कीमत में कटौती	रेंज	-	-	10-20

51. यह देखा गया है कि अलग अलग रूप से पैक की गई वस्तुओं के लिए संपूर्ण रूप में लिये जाने पर कीमत में कटौती जांच की अवधि में यूरोपीय संघ, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से सकारात्मक है जबकि यह संयुक्त राज्य के लिए नकारात्मक है।

ii. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

52. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुकेगी जो अन्यथा हुई होती, घरेलू उद्योग ने नीचे दिये गये अनुसार क्षति की अवधि की तुलना में लागतों और कीमतों पर परिवर्तन के लिए सूचना दी है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
आयातों की पहुंच कीमत – यूरोपीय संघ	रु./ मी. ट.	73,459	44,936	88,144	50,956
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	120	69

आयातों की पहुंच कीमत – सिंगापुर	रु./ मी. ट.	66,331	36,814	44,881	50,803
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	68	77
आयातों की पहुंच कीमत – दक्षिण अफ्रीका	रु./ मी. ट.	80,507	53,452	50,997	51,612
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	63	64
आयातों की पहुंच कीमत – संयुक्त राज्य अमेरिका	रु./ मी. ट.	51,450	-	-	56,864
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	-	111
आयातों की पहुंच कीमत – संबद्ध देश	रु./ मी. ट.	69,829	42,327	45,065	50,904
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	65	73
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	69	76
घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	74	76

53. यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पहुंच मूल्य में कमी आई है। बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत में भी आधार वर्ष की तुलना में क्षति के अवधि के दौरान गिरावट आई है। लेकिन आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि (आधार वर्ष जब पहुंच मूल्य लागत और बिक्री कीमत की तुलना में अधिक थी, को छोड़कर) के दौरान घरेलू उद्योग की लागत कीमत और बिक्री कीमत से कम है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि बिक्री की कीमत बिक्री की लागत से कम है जो इस बाजार में कम कीमतों पर आयातों के होने के कारण है। इस कारण से यह देखा गया है कि आयातों का घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी और दबावकारी प्रभाव पड़ रहा है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

54. कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य के साथ क्षति रहित कीमत की तुलना करते हुए की गई है।

विवरण	यू ओ एम	ई यू	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	यू एस ए
आयात की मात्रा	मी. ट.	6,996	7,184	338	20
आयात का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	50,956	50,803	51,612	56,864
क्षति-रहित कीमत*	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	5-15	5-15	5-15	5-15

(*देशवार क्षति रहित कीमत का निर्धारण पृथक रूप से थोक और पैक किये गये वस्तुओं के लिए किया गया है और भारत औसत आयातों की मात्रा के आधार पर लिया जाता है।)

55. क्षति रहित कीमत से पहुंच मूल्य (पाटनरोधी शुल्क को जोड़े बिना) की तुलना से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

IV. घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड

56. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

i. उत्पादकता, क्षमता, क्षमता का उपयोग बिक्री की मात्रा

57. उत्पादकता, क्षमता, क्षमता का उपयोग बिक्री की मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
क्षमता	मी. ट.	22,500	22,500	22,500	22,500
उत्पादन	मी. ट.	19,816	22,311	21,974	22,263
क्षमता का उपयोग	%	88.07	99.16	97.66	98.95
घरेलू बिक्री	मी. ट.	19,937	22,401	21,620	22,341

58. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रही है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

59. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
संबद्ध देशों का आयात	%	13.54	14.74	6.27	8.10
वे देश जिस पर पहले से ही शुल्क लग रहे हैं	%	68.08	57.63	35.07	23.53
अन्य देश	%	1.30	12.30	42.42	50.02
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	%	13.04	13.71	13.33	12.44
समर्थक	%	4.03	1.62	2.91	5.91
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

60. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई जबकि घरेलू बिक्री के बाजार हिस्से में भी कमी आई है। अन्य देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता यह दावा रहा है कि पाटित आयात एक देश से दूसरे देश तक बदलते रहते हैं जब कभी इन शुल्कों को लगाया जाता है और वे समाप्त हो जाते हैं।

iii. माल सूची

61. संबद्ध वस्तुओं की माल सूची से संबंधित आंकड़े जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है :

यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	57	110	167

iv. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ

62. घरेलू उद्योग का लाभ/ हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ नीचे दिए अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
लाभ/ (हानि) – घरेलू	■ / मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(159)	146	(42)
लाभ/ (हानि) – घरेलू	■ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(141)	135	(38)
नकद लाभ	■ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(172)	194	(25)
नियोजि पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(200)	263	(84)

63. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को 2016-17 को छोड़कर क्षति की पूरी अवधि के दौरान हानि हो रही है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि ये हानि पाटित आयातों के सतत रूप से मौजूद रहने के कारण वह है। घरेलू उद्योग को हानि में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कमी आई है। कंपनी को जांच की अवधि के दौरान नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक लाभ का सामना करना पड़ता है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

64. रोजगार और मजदूरी नीचे दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
प्रति इकाई मजदूरी	■ / मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	88	93
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	110	113
उत्पादकता/ कर्मचारी	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	101	99
उत्पादकता/ दिवस	मी. ट.	57	64	63	64
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	111	112

65. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति इकाई मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति की अवधि में आंशिक रूप से कमी आई है जबकि प्रतिदिन उत्पादकता में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

पाटन मार्जिन

66. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम स्तरों से ऊपर है।

झ. क्षति मार्जिन

67. सिंगापुर के उत्तर देने वाले सहयोगी उत्पादक निर्यातक के लिए क्षति मार्जिन की गणना आयात के आंकड़ों से अन्य के लिए और यथा सत्यापन किये संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य से क्षति रहित कीमत की तुलना करते हुए की गई है।

विवरण	एल वी	एन आई पी	क्षति मार्जिन		
	रु. / मी. ट.	रु. / मी. ट.	रु. / मी. ट.	%	रेंज
मित्सुबु फेनोल्स सिंगापुर पीटीई. लिमि.	***	***	***	***	5 - 15
यूरोपीय संघ	50,956	***	***	***	5 - 15
दक्षिण अफ्रीका	51,612	***	***	***	5 - 15
संयुक्त राज्य अमेरिका	56,864	***	***	***	5 - 15

(*देशवार क्षति रहित कीमत का निर्धारण थोक और पैक किये हुए में आयातों की भारत औसत के आधार पर किया गया है।)

ब. क्षति के संबंध में निष्कर्ष

68. इस प्रकार से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। आयातों में जांच की अवधि की बाद की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। पाटित आयातों का कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संबंध में प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को बहुत अधिक कम कीमत पर बिक्री के कारण भी नुकसान हो रहा है। निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के पास माल सूची में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को सतत रूप से क्षति उठानी पड़ी है।

ट. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना**घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

69. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है :

- क. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारी मात्रा में क्षमताएं रहती हैं।
- ख. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य उत्पादन क्षमताएं हैं।
- ग. संबद्ध देशों से निर्यातकों का पूरे विश्व में बहुत अधिक निर्यात उन्मुखीकरण है जिसे कुल निर्यातों में वृद्धि के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- घ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है और इस कारण से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने की बावजूद, चीन के निर्यातकों ने पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात करना जारी रखा है। इस प्रकार से यह बहुत संभव है कि इस प्रकार के शुल्क के न रहने की स्थिति में भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहेगा।
- च. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम स्तरों से अधिक है। संबद्ध देशों ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करना जारी रखा है।

पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि आयात पाटित कीमतों पर होना जारी रहेगा और इससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

- छ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अब तक अनेक मध्यावधि और निर्णायक समीक्षा जांचों का निर्णय लिया है। मध्यावधि और निर्णायक समीक्षा में क्षति का निर्धारण वही है अथवा एक जैसा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में समान रूप से स्थित परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाये जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, माननीय न्यायाधिकरण के अनेक निर्णय वर्तमान मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में सीधे तौर पर लागू होते हैं।
- ज. विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने 20-20 वर्षों के बाद भी पाटनरोधी शुल्कों को लगाये रखा है। घरेलू उद्योग ने इस प्रकार के मामलों और देशों जिन्होंने 20-30 वर्षों से आगे तक इन शुल्कों को लगाया है कि सूची रिकार्ड में रखी है।
- झ. भारत पर 1992 से ब्राजील में जूट के थैलों के इसके निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। यद्यपि ब्राजील में जूट के थैलों का कोई ज्ञात निर्यात नहीं हुआ है फिर भी इन शुल्कों को इस मामले में बाद की निर्णायक समीक्षाओं में लगाया गया है।
- ञ. पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने की बावजूद, घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर उचित लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाया है। लाभप्रदता में और आगे किसी प्रकार की गिरावट से घरेलू उद्योग को बहुत अधिक नुकसान होगा।
- ट. यह स्पष्ट है कि यदि इस शुल्क को बंद कर दिया जाता है तब ये आयात पाटित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से को तब तक बनाये रखने की स्थिति में नहीं होंगे जब तक यह लाभप्रद कीमतों से कम कीमत पर और इसके विपरीत बिक्री करने का इच्छुक न हो।
- ठ. घरेलू उद्योग के कुल लाभ में गिरावट आयेगी और निवेश पर इसका लाभ आगे और कम हो जायेगा। इस कारण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबद्ध आयातों के कारण शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- ड. व्यापार नोटिस सं. 02/2017 निर्णायक समीक्षा दायर करने के लिए एक अनिवार्य मानदंड के रूप में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों को प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं करता है, जिसके न होने पर जांच समाप्त हो जायेगी। इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े वर्तमान मामले में गुण दोष को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं।
- ढ. अतिरिक्त क्षमता, स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं और निर्यात उन्मुखीकरण जैसी संभावना के मानदंडों के लिए सभी साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं।
- ण. घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ रही है। यदि ऐसा निर्धारण किया जाये कि घरेलू उद्योग को क्षति से हानि नहीं हो रही है तब संभावना पर भी विचार किया जाना है।
- त. स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता की गणना उस क्षमता के रूप में की जाती है जिसका उपयोग निर्यातकों द्वारा नहीं किया गया है, वह क्षमता जिसके बिना और उसके लिए साक्ष्यों को उपलब्ध कराया गया है। उत्पादक/ निर्यातक किसी साक्ष्य के साथ उसका खंडन कर पाने में सक्षम नहीं हुए थे।
- थ. मित्सुई ग्रुप ने निर्यातक की प्रश्नावली के भाग 2 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जो उनकी क्षमताओं, क्षमता विस्तार, लेन देन वार तीसरे देश में निर्यात, घरेलू बिक्री, माल सूची आदि जो उनकी संभावना के व्यवहार का द्योतक है, पर निर्यातक से सूचना की मांग करता है।
- द. चीन में वैश्विक निर्यात में धीरे धीरे कमी आ रही है उसका कारण चीन में हाल में किया गया क्षमता विस्तार है। स्व-पर्याप्तता के कारण, चीन ने आयातों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और इस कारण से भारत एक बहुत अधिक आकर्षक बाजार बना हुआ है।

विरोधी पक्षकारों का दृष्टिकोण

70. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध का सारांश यहां नीचे दिया गया है :
- क. जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और इस कारण से संभावना का निर्धारण संभव नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इन आंकड़ों को अस्वीकार कर दें और जांच को समाप्त कर दें।
 - ख. याचिकाकर्ताओं ने संभावना न होने को सिद्ध करने के लिए निर्यातकों पर प्रमाण का दायित्व डालने की कोशिश की है जबकि इस कथन का कोई कानूनी आधार नहीं है।
 - ग. जांच की अवधि के बाद की अवधि के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और इस कारण से उसका आकलन नहीं किया जा सकता है कि संबद्ध वस्तुओं का वर्तमान में पाटन किया जा रहा है अथवा नहीं।
 - घ. संबद्ध देशों में कथित वृहत क्षमताओं के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य हो तब सिंगापुर में क्षमताओं को तीसरे देशों द्वारा खपाया जा रहा है। इसके अलावा, इन देशों में क्षमता का कोई विस्तार नहीं हुआ है, अतः इसमें कोई संभावना शामिल नहीं है।
 - ङ. स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता की गणना कथित क्षमताओं से संबद्ध देशों में मांग को केवल घटाकर की जाती है। इस कारण से इस गणना को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।
 - च. निर्यातकों की कथित उच्च निर्यात उन्मुखीकरण का साक्ष्य बिलकुल भी नहीं है।
 - छ. तीसरे देशों में सिंगापुर निर्यात कीमतें पाटनरोधी शुल्क के जोड़े जाने के बाद भी भारतीय कीमतों से तुलनीय हैं। यदि आकर्षकता हो तब आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई होती। चूंकि निर्यात अंतर बहुत अधिक नहीं है अतः शुल्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
 - ज. संबद्ध देशों में माल सूची के स्तरों के संबंध में जांच की अवधि के बाद की अवधि का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही इसके लिए ऐसा कोई अन्य साक्ष्य है।
 - झ. चीन संबद्ध वस्तुओं का एक निवल आयातक है और इसका कीमत निर्धारण भारत जैसा ही है और इस कारण से वह निर्यातकों के लिए बहुत अधिक आकर्षक स्थान है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

71. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध II (vii) के संबंध में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच की है। इस नियमावली के अनुबंध II के नियम (vii) में अन्य बातों के साथ साथ चार कारकों के लिए प्रावधान है जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, अर्थातः
- क. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि का एक बहुत अधिक दर;
 - ख. किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा एक आसन्न, वास्तविक क्षमता वृद्धि;
 - ग. क्या ये आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक ह्रासकारी अथवा दबावकारी प्रभाव पड़ेगा और संभवतः आगे से आयातों के लिए मांग में वृद्धि होगी; तथा
 - घ. जांच की जा रही वस्तु की सूची।
- इसके अलावा, प्राधिकारी ने किसी अन्य संगत कारक जिसका पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना पर प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।
72. प्राधिकारी के ध्यान में सभी कारकों को लाया गया है और इसकी जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

है। चूंकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपने आर्थिक मानदंडों में वृद्धि देखी है, इस कारण से इस तथ्य का निर्धारण करना और अधिक संगत हो जाता है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति यदि ये शुल्क निष्प्रभावी हो जाते हैं तब पाटन के कारण फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार विभिन्न सूचना पर विचार किया है। संभावना के मानदंडों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

I. जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात

73. भारत ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयातों की जांच करने के लिए, अन्य डी जी सी आई एंड एस से आंकड़े प्राप्त किये हैं और उससे यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयातों में जांच की अवधि की तुलना में और अधिक वृद्धि हुई है।

आयात की मात्रा	यू ओ एम	पी ओ आई	जांच की अवधि के बाद की अवधि (अप्रैल 18 से दिसंबर 18)	जांच की अवधि के बाद की अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	मी. ट.	14,539	30,098	40,131
यूरोपीय संघ	मी. ट.	6,996	6,169	8,225
सिंगापुर	मी. ट.	7,184	15,638	20,851
दक्षिण अफ्रीका	मी. ट.	338	666	888
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. ट.	20	7,625	10,167

74. इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध देशों से कीमतों में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि की तुलना में कमी आई है। पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में, इन आयातों के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आने की संभावना है।

II. आधिक्य उत्पादन क्षमताएं

75. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में आधिक्य उत्पादन क्षमताओं के संबंध में सूचना दी है :

क्र. सं.	निर्यातक	देश	क्षमता मी. ट. में
1	आई एन ई ओ एस	जर्मनी	415000
2	आई एन ई ओ एस	बेल्जियम	395000
3	बोरेलिस	यूरोपीय संघ	120000
4	वरसलिस	यूरोपीय संघ	185000
5	नोवापेक्स	यूरोपीय संघ	108000
6	सी ई एस पी ए	यूरोपीय संघ	370000
7	अन्य	यूरोपीय संघ	158000
9	शैल	संयुक्त राज्य अमेरिका	360000
10	आई एन ई ओ एस	संयुक्त राज्य अमेरिका	330000
11	होनीवेल	संयुक्त राज्य अमेरिका	310000
12	डी ओ डब्ल्यू	संयुक्त राज्य अमेरिका	180000
13	एस ए बी आई सी	संयुक्त राज्य अमेरिका	208000

क्र. सं.	निर्यातक	देश	क्षमता मी. ट. में
14	ह्वरहिल	संयुक्त राज्य अमेरिका	173000
15	एक्सअल	संयुक्त राज्य अमेरिका	140000
16	डी ओ डब्ल्यू	संयुक्त राज्य अमेरिका	77000
19	मित्सुई फेनोल	सिंगापुर	180000
20	सासोल सोलवेंट्स	दक्षिण अफ्रीका	175000
21	अन्य		36740
22	कुल		3920740

स्रोत आईसीआईएस रिपोर्ट

76. सारांश में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार देखी जा सकती है -

विवरण	यूरोपीय संघ	संयुक्त राज्य अमेरिका	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	कुल
क्षमता	18,41,000	18,14,740	1,80,000	1,75,000	40,10,740
मांग	17,00,000	14,00,000	2854	65,200	31,65,200
आधिक्य	1,41,000	4,14,740	1,77,146	1,09,800	8,45,540

77. घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि संबद्ध देशों में उनके अलग अलग बाजार में मांग से अधिक विशाल उत्पादन क्षमताएं आधिक्य मात्रा को परिवर्तित किये जाने की संभावना को दर्शाता है।
78. निर्यातकों ने यह उल्लेख किया है कि किसी देश में “आधिक्य क्षमता” का परस्पर यह आशय नहीं होता है कि पाटन की संभावना है। आज की तारीख के अनुसार संबद्ध देशों में उत्पादन पहले से ही अलग अलग देशों में मांग से बंधी हुई है। उत्पादन की गई मात्राएं निष्क्रिय नहीं पड़ी हैं, जिससे की इसे तत्काल भारत में परिवर्तित किया जायेगा जिसकी आशंका घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त की गई है।
79. हालांकि यह नोट किया जाता है कि इन निर्यातकों ने यह दर्शाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि इन निर्यातकों के पास अलग अलग देशों में पहले से ही मांग के अनुरूप क्षमताएं हैं। वास्तव में यह देखा गया है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि में सिंगापुर से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है (आयात जांच की अवधि के दौरान के स्तरों का लगभग 3 गुणा था)। इसके अलावा सीमा शुल्क आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि तीसरे देशों में सिंगापुर से भारत और आसत निर्यात कीमत भारत में निर्यात कीमत की तुलना में कम है और अनेक देशों में भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर बहुत अधिक निर्यात हुए हैं। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं मौजूद हैं और पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में इस अतिरिक्त मात्राओं को भारतीय बाजार में भेजे जाने की संभावना है।

iii. विदेशी उत्पादकों का उच्च निर्यात उन्मुखीकरण

80. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों द्वारा किये गये निर्यात का व्यौरा प्रस्तुत किया है जिसे नीचे दर्शाया गया है :

संबद्ध देश	यू ओ एम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
यूरोपीय संघ	मी. ट.	692,778	708,625	705,406	826,805
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. ट.	162,863	173,173	124,501	117,989

सिंगापुर	मी. ट.	165,764	138,242	170,237	127,887
दक्षिण अफ्रीका	मी. ट.	69,376	74,645	75,038	73,327
कुल	मी. ट.	1,090,782	1,094,686	1,075,182	1,146,008

81. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों द्वारा निर्यात इन वर्षों के दौरान बढ़ता रहा है और यह उनके उच्च निर्यात उन्मुखीकरण को दर्शाता है। सिंगापुर निर्यातकों ने इसका विरोध किया है कि विश्वव्यापी उच्च निर्यात उन्मुखीकरण भारत में बढ़े हुए पाटन की इसकी संभावना का द्योतक नहीं है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों में निर्यात उस कीमत पर हुआ है जो भारत में किये गये निर्यातों की तुलना में कम है, जांच की अवधि की बाढ़ की अवधि में सिंगापुर से आयात जांच की अवधि में किये गये आयातों का लगभग 3 गुणा है और भारत में निर्यात कीमत की तुलना में कम कीमत पर अनेक देशों में बहुत अधिक निर्यात हुए हैं।

iv. एक बाजार के रूप में भारत की आकर्षकता

विवरण	यू ओ एम	यूरोपीय संघ	संयुक्त राज्य अमेरिका	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका
आयातों का पहुंच मूल्य	▪ /मी. ट.	50,956	56,864	50,803	51,612
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	▪ / मी. ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	▪ / मी. ट.	***	***	***	***

82. यह देखा जा सकता है कि आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री कीमत से कम है। निर्यातकों ने भारतीय बाजार की आकर्षक कीमत का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है क्योंकि उन कीमतों जिस पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात तीसरे देशों में किया जाता है, भारत से तुलनीय है। इसके अलावा प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से तीसरे देशों में किये गये निर्यातों की कीमत की जांच की है और यह पाया गया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक अनेक देशों में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उन कीमतों पर कर रहे हैं जो भारतीय कीमतों की तुलना में कम है और उसके माध्यम से भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा भारत में पाटित कीमतों पर इस उत्पाद का निर्यात करने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ठ. संभावना के संबंध में निष्कर्ष

83. उपर्युक्त तथ्यों और रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

ड. कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

84. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योगों का अनुरोध का सारांश यहां नीचे दिया गया है:

- कीमत में कटौती सभी देशों से सकारात्मक है, वास्तव में पहुंच कीमत बिक्री की लागत से भी कम है।
- घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के द्वारा दबाव पड़ रहा है।
- घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को आयातों के अनुरूप रखने के लिए बाध्य हैं और परिणामस्वरूप इसे बहुत अधिक कीमत में क्षति हो रही है।
- पाटनरोधी शुल्कों के रहने के बावजूद पाटन जारी रहा है।

- ड. वह अवधि जिसके दौरान शुल्क लागू रहा है, पर इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए विचार करना संगत नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- च. भारत सरकार ने एच ओ सी एल के लिए एक पुनर्गठन योजना का अनुमोदन किया है, जो गैर व्यवहार्य इकाईयों की संरचित बंदी का कार्य करेगा और ऐसिटोन के प्रभावी संयंत्र के लिए राजस्व प्राप्त करेगा। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान, यह संयंत्र 98 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर चल रहा था।
- छ. याचिकाकर्ताओं ने अन्य देशों से पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच के लिए एक पृथक याचिका दायर की है। हालांकि, चूंकि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देशों की पहुंच कीमत अन्य देशों की पहुंच कीमत से बहुत अधिक तुलनीय है, इस तथ्य को दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने पर संबद्ध देशों से क्षति की भारी संभावना है।
- ज. एच ओ सी एल की रुग्णता कम प्रदर्शन करने वाले रासायनिक संयंत्र के कारण थी। भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये नए पुनर्गठन योजना के अंतर्गत, रासायनिक संयंत्र को भेज दिया जायेगा और उसकी विक्री से प्राप्त राशि को विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले कोचि संयंत्र को दिया जायेगा।
- झ. कोच्चि और रासायनिक संयंत्रों के लाभों को दर्शाते हुए अलग अलग विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि कोच्चि संयंत्र कार्यक्षम है।

विरोधी पक्षकारों का दृष्टिकोण

85. कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

- क. शुल्क की अवधि प्रासंगिक नहीं है जैसा की याचिका में जोर देकर कहा गया है और याचिकाकर्ता आदर्श से कम स्तरों पर कार्य करेंगे चाहे जब तक शुल्क चलता रहे।
- ख. एच ओ सी एल की क्षति अपने स्वयं द्वारा उठायी गई क्षति की प्रकृति का है और यह उनकी अपनी अक्षमताओं के कारण हुआ है।
- ग. जापान और थाइलैण्ड के आयातों की कीमत अन्य देशों के समान है। शुल्क के समाप्त होने के बाद, थाइलैण्ड से आयात कुल आयातों का 42 प्रतिशत होता है और ये कीमतें अन्य देशों से अनुरूप हैं। इस कारण से, शुल्कों के जारी रहने का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है।
- घ. एच ओ सी एल 10 वर्षों से अधिक तक अपनी अक्षमताओं को कम करने के लिए पाटनरोधी शुल्क के भंडार के साथ कार्य कर रहा है। विस्तार करने और लागतों को कम करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण योजनाएं रक्षोपाय जांच के दौरान उपलब्ध कराये गये थे परंतु क्षमता 1999 से वही रही है। यह दर्शाता है कि वह अपनी कमियों को दूर कर पाने में सक्षम नहीं है।
- ड. एच ओ सी एल का लंबे समय से खराब काय निष्पादन की छानबीन किये जाने की आवश्यकता है। पाटनरोधी शुल्क की सुविधा रहने के बावजूद उन्हें 2015-16 तक रुग्ण कंपनी के रूप में माना गया है।
- च. जांच की अवधि के दौरान इस देश में विशाल मांग आपूर्ति अंतर है और यही इन आयातों का मुख्य कारण है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

86. यह जांच इस तथ्य को दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन है। संभावना का विश्लेषण उस स्थिति को भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति और अधिक गहन हो जायेगी यदि पाटनरोधी शुल्क मौजूद रहना समाप्त हो जाता है। मांग और आपूर्ति के अंतर के संबंध में चिंता का समाधान संभावित रूप से अन्य भारतीय उत्पादक द्वारा किया जाना है जो इस याचिका का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा, यह पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं में प्रवेश करने के लिए निर्यातक देशों के वास्ते कारण नहीं हो सकता है।

ढ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

87. प्रकट पश्चात् अनुरोध घरेलू उद्योग से और सिंगापुर के निर्यातक से प्राप्त हुए हैं। कोई अन्य विदेशी उत्पादक/निर्यातक अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दे व्यापक रूप से दोहराये गये हैं। उनमें उठाये गये मुद्दों का जांच के दौरान पूर्व में भी उठाया गया है और उसका

समाधान भी उपयुक्त रूप से किया गया है। हालांकि, स्पष्टता के वास्ते, इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की जा रही है :

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

88. प्रकटन विवरण जारी किये जाने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

- क. प्रकटन विवरण आवश्यक तथ्यों का पर्याप्त प्रकटन नहीं होता है। यह पाटन के जारी रहने की संभावना पर मौन है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर संभावना के संबंध में अनुरोध किया है। उस पर इस प्रकटन में विचार नहीं किया गया है।
- ख. विस्तृत अनुरोधों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण तर्कों जिन पर प्रकटन विवरण में विचार नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए (1) मित्सू द्वारा निर्णायक समीक्षा प्रश्नावली का भाग 2 प्रस्तुत नहीं करना (2) निर्यातकों द्वारा दावा किये गये अत्यधिक गोपनीयता (3) पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में अनुरोध।
- ग. प्राधिकारी ने एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना है। यह तथ्य कि एच ओ सी एल ने विचाराधीन उत्पाद का निर्माण अंतराल पर नहीं किया है, को घरेलू उद्योग के रूप में एच ओ सी एल को बाहर करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है।
- घ. उत्तर देने वाले उत्पादक ने संबंधित प्रतिष्ठान के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इस कारण से यह अपेक्षित है कि निर्यात कीमत का समायोजन संबंधित व्यापारी के एस जी ए और लाभ के लिए किया जाए। निर्धारित निर्यात कीमत का उल्लेख बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। निर्यातक ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अर्तदेशीय भाड़े, अर्तदेशीय बीमा, बंदरगाह और रख-रखाव प्रभावों आदि के आधार पर कोई समायोजन की सूचना नहीं दी है।
- ङ. चूंकि सिंगापुर के उत्पादक ने थोक और पैक किये हुए दोनों सामग्रियों की आपूर्ति की है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की अलग अलग तुलना थोक और पैक किये हुए उत्पाद के लिए की गई है। यदि ऐसा नहीं है तब पैक किये हुए और थोक सामग्री की लागत और कीमत में अंतर का मानना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- च. विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद वर्तमान जांच में पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।
- छ. याचिकाकर्ता यह समझते हैं कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए क्यूमिन हेतु सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई है। यदि हां तो यह स्पष्ट रूप से अनुबंध III के प्रावधानों से परे है कैप्टिव इनपुट के उत्पादन की लागत और न ही मानदंड के अनुसार उत्पादन की लागत पर विचार किया जाना अपेक्षित है।
- ज. क्षति रहित कीमत का प्रकटन यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने कच्चे माल की खपत में अक्षमताओं तक सीमित रहने मात्र के बजाय जांच की अवधि में कीमतों के दबावकारी प्रभाव को वास्तव में लागू किया है। इसके फलस्वरूप क्षति रहित कीमत दबाव वाली कीमतों की तुलना में कम हो गई। प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वह कृपया क्षति रहित कीमत की गणना और उसके फलस्वरूप क्षति मार्जिन को संशोधित करें।
- झ. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे उसी शुल्क को अमरीकी डालर के रूप में भी लगायें।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

89. प्रकटन विवरण के जारी किये जाने के पश्चात् घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

- क. प्रकटन विवरण घरेलू उद्योग की संरचना के बारे में स्पष्ट नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की संरचना जांच की पूरी अवधि के दौरान बदलती रही। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा विश्वास किये गये आंकड़े इस याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई प्रथम याचिका जिसे एस आई गुप, दीपक फेनोलिक द्वारा दायर किया गया था, के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

- ख. प्रकटन विवरण से निर्यातक यह विश्वास करते हैं कि प्राधिकारी ने एस आई ग्रुप, दीपक फेनोलिक और एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग के रूप में माना है और निर्यातक उस पर आपत्ति करते हैं क्योंकि एक गैर उत्पादक देश को घरेलू उद्योग के सदस्य के रूप में माना नहीं जा सकता है। दीपक फेनोलिक ने अपना उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस कारण से इसे घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ग. मांग में वृद्धि हुई है परंतु संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में कमी आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है और इस कारण से घरेलू उद्योग तथा समर्थक एच ओ सी एल पर संबद्ध देशों से आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- घ. कीमत में कटौती पैक किये हुए और थोक के लिए सिंगापुर के लिए सकारात्मक है। प्राधिकारी ने पूर्व के वर्ष के लिए कीमत में कटौती नहीं दी है।
- ङ. घरेलू उद्योग बिक्री की लागत के अनुरूप अपनी कीमतों में परिवर्तन नहीं कर पाया है। सिंगापुर से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत की तुलना में अधिक है। इस कारण से कोई ह्रास अथवा दबाव नहीं हुआ है।
- च. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और एस आई ग्रुप तथा एच ओ सी एल की वार्षिक रिपोर्ट उसी का संकेत देते हैं।
- छ. जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े इन हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और उनका उपयोग जब कभी भी घरेलू उद्योग के लिए उपयुक्त हुआ प्रकटन विवरण में किया गया है। इस तथ्य के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं कि क्या यह आयात पाटित कीमतों पर हुआ है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर लाभ, लाभप्रदता और अन्य महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन संबंधी मानदंड दृष्टिगत होते हैं।
- ज. यद्यपि सतत पाटन हुआ है फिर भी क्षति के सतत रूप से होने अथवा उसका फिर से होना मौजूद नहीं है। घरेलू उद्योग के आयातों और कार्य निष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। यदि कोई क्षति हुई भी हो तो वह एच ओ सी एल के कारण हुई है।
- झ. स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं की जांच किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजार की उपलब्धता के बाद की जानी है। घरेलू उद्योग ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि अन्य बाजारों के पास अतिरिक्त निर्यातों को खपाने की क्षमता है।
- ञ. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि तीसरे देशों में सिंगापुर की कीमतों की तुलना भारत में कीमतों से की जा सकती है। भारत और चीन में कीमतों की तुलना वास्तव में की जा सकती है। चीन भारी मात्रा में निर्यात के कारण सिंगापुर के लिए एक अधिक आकर्षक बाजार है।
- ट. कारणात्मक संबंध का विश्लेषण करते समय प्राधिकारी द्वारा विचार किये गये किसी नये तथ्य की जानकारी निर्यातकों को होनी चाहिए क्योंकि इस प्राधिकारी ने एच ओ सी एल और इसके कार्य निष्पादन के संबंध में प्रकटन विवरण में विभिन्न तथ्यों को प्रकट नहीं किया है। इस तथ्य का विश्लेषण करने के लिए कारणात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्या लागू शुल्क को जारी रखा जाये अथवा उसे समाप्त कर दिया जाये।
- ठ. प्राधिकारी को इस तथ्य की भी जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति गैर संबद्ध देशों से एस आई ग्रुप के आयातों के कारण हुई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियां/ अनुरोध अधिकांशतः उनके अनुरोधों की पुनरावृत्ति है जिसकी पहले ही जांच उपयुक्त रूप से और समुचित रूप से की गई है और उसका समाधान उचित रूप से प्रकटन विवरण अथवा वर्तमान जांच परिणाम के संगत पैराओं में किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में नीचे दिये गये अनुसार विचार करते हैं:
- क. यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर के केवल एक उत्पादक ने प्राधिकारी को उत्तर दिया है। अन्य संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है। सिंगापुर के उत्तर देने वाले उत्पादक

अथवा निर्यातक ने विभिन्न तीसरे देशों को अपने निर्यातों के संबंध में निर्धारित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

- ख. जहां तक घरेलू उद्योग की संरचना का प्रश्न है, प्रकटन विवरण में इस संरचना का स्पष्ट रूप से उल्लेख था और इसे आगे स्पष्ट किया गया था कि मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमि. और मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमि. द्वारा मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमि. (एच ओ सी एल) से समर्थन पत्र के साथ साथ यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चूंकि मैसर्स दीपक फेनोलिक ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू नहीं किया था और एच ओ सी एल ने जांच की अवधि के दौरान सतत् रूप से उत्पादन नहीं किया है, अतः केवल एस आई ग्रुप को वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। घरेलू उद्योग की संरचना के संबंध में प्रकटन विवरण में कोई आशंका नहीं है।
- ग. जहां तक याचिका और प्रकटन विवरण के बीच आंकड़ों में अंतर का प्रश्न है, जबकि स्वयं निर्यातक ने इस बात का उल्लेख किया है कि यदि एस आई ग्रुप को किसी भी स्थिति में माना जाता है, तब आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है, प्राधिकारी ने वर्तमान उद्देश्यों से सत्यापन किये गये आंकड़ों पर विचार है।
- घ. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किये गये पाटन और क्षति की संभावना के संबंधित तथ्यों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उसकी जांच उपयुक्त रूप से अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किये गये संगत पैराओं में की जा चुकी है।
- ङ. जहां तक हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये इस अनुरोध का प्रश्न है कि प्राधिकारी ने सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रकटन विवरण में नियम 16 के संबंध में सभी आवश्यक तथ्य निहित थे।
- च. जहां तक क्षति रहित कीमत की गणना के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क का प्रश्न है, संगत गणना याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई है और यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गयी सूचना और रिकार्ड के आधार पर यह गणना है। कंपनी ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी लगातार वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार फेनोल, एसीटोन क्यूमि की उत्पादन की लागत पर और बिक्री की लागत, आदि को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को घोषित कर रही है। क्यूमि एक तैयार उत्पाद है और कंपनी इसे खुले बाजार में बेच रही है। क्यूमि बेंज़ीन और प्रोपलीन से निर्मित होता है और इसे फिनोल और एसीटोन के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है। एनआईपी के निर्धारण के लिए, एसीटोन का उत्पादन करने के लिए क्यूमि की खपत कंपनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट से ली गई है। क्यूमि का सामान्यीकरण अनुबंध III के अनुसार किया जाता है। उसी के मद्देनजर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एनआईपी उपयुक्त है।
- छ. जहां तक सिंगापुर के सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के लिए निर्यात कीमत की गणना का प्रश्न है, प्राधिकारी ने दायर की गई और सत्यापित की गई सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। निर्यातक द्वारा उठाये गये खर्च (ढुलाई खर्च, कमीशन, बैंक शुल्क और ऋण की लागत सहित) को विधिवत रिपोर्ट किया गया था, सत्यापित किया गया था और निर्यातक के संगत एस जी एंड ए खर्च तथा लाभ मार्जिन एवं निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किये गये कारखाना पश्चात् खर्च के लिए विधिवत समायोजित किया गया था। इसको देखते हुए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई कारखानागत कीमत उपयुक्त है।
- ज. जहां तक थोक और पैक किये हुए बिक्री के लिए पृथक रूप से परिकलन किये जाने का प्रश्न है। प्रकटन विवरण में इसे पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राधिकारी ने थोक और पैक की हुई बिक्री के लिए पृथक रूप से पाटन और क्षति के लिए मार्जिन का निर्धारण किया है और जहां भी आवश्यक हुआ तुलना किये जाने के लिए उपयुक्त समायोजन किये गये हैं।
- झ. जहां तक आयातों में गिरावट का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा में जांच की अवधि की बाद की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क भी दिया है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में और आगे वृद्धि हुई है।

- ज. जहां तक क्षति की अवधि की तुलना में कीमत में कटौती का प्रश्न है यह नोट किया जाता है कि कीमत में कटौती का निर्धारण केवल जांच की अवधि के लिये किया जाना अपेक्षित है।
- ट. जहां तक कीमत ह्रास/ कीमत न्यूनीकरण के न होने का प्रश्न है जैसा कि वहां ऊपर नोट किया गया है, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर स्पष्ट रूप से दबाव पड़ा था, जिसके फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहां घरेलू उद्योग को पुनः पूर्व के वर्ष में लाभों की स्थिति से वित्तीय हानि होना आरंभ हो गया।
- ठ. जहां तक अलग अलग रूपों के लिए पृथक रूप से कम कीमत पर बिक्री को प्रकट न किये जाने का प्रश्न है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रकटन विवरण में अलग अलग रूपों के लिये उन्हें पृथक रूप से दर्शाना आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी ने पृथक तुलना की है और उसकी भारत औसत को प्रकटन विवरण और इन जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से दर्शाया गया है।
- ड. जहां तक जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों को प्रकट किये जाने का प्रश्न है, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया है। इसके अलावा, स्वयं प्रकटन विवरण में इन्हें उपयुक्त रूप से प्रकट किया गया है।
- ढ. जहां तक किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यातों की उपलब्धता पर विचार करने के बाद स्वतंत्र रूप से बिक्री किये जाने योग्य क्षमताओं पर विचार करने का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने तीसरे देशों में ठोस प्रतिबद्धताओं को दर्शाने के बाद स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं के न होने को सिद्ध किया है। वास्तव में ये आंकड़े सिंगापुर से और सम्पूर्ण रूप से संबद्ध देशों से आयातों में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाते हैं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि तीसरे देशों के बाजार में कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं है।

ण. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

91. प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में उचित प्रतियोगिता को इन पाटनरोधी उपायों से कम नहीं किया जायेगा। इसके प्रतिकूल पाटनरोधी उपायों को लगाये जाने से पाटन प्रथाओं के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प उपलब्ध कराये रखने में मदद मिल सकेगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाये जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं किया जायेगा।

त. निष्कर्ष

92. उठाये गये मुद्दों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और किये गये अनुरोधों के संबंध में तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में प्राधिकारी के समक्ष यथा रिकार्ड किये गये उपलब्ध तथ्यों और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :
- विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात किया जाना जारी है
 - घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण सतत् क्षति हुई है
 - पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सतत् क्षति हुई है और यदि संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्कों समाप्त कर दिया जाता है तब इसके जारी रहने की संभावना है।
 - यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को इस चरण में समाप्त होने दिया जाता है तब रिकार्ड पर सूचना पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
 - एक उत्पादक निर्यातक ने समीक्षा जांच के दौरान सिंगापुर से सहयोग किया है। मैसर्स मित्सु फिनोल्स सिंगापुर पीटीई. लिमि. ने भारत में सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया है और पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

- (vi) यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक निर्यातक ने वर्तमान समीक्षा जांच में सहयोग नहीं किया है। ये उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि इन देशों से आयात उन कीमतों पर किया गया है जो सामान्य मूल्य से कम हैं।

थ.सिफारिशें

93. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद की यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाये तब पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों, पाटन और क्षति की संभावना के पहलु के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि सभी संबद्ध देशों के विरुद्ध शुल्क को जारी रखा जाना अपेक्षित है।
94. कमतर शुल्क नियम के संबंध में प्राधिकारी पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि सिंगापुर से उत्तर देने वाले सहयोगी उत्पादक निर्यातक के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके और सभी अन्य गैर सहयोगी प्रतिष्ठानों के संबंध में पूर्व का शुल्क लगाया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जिसे नीचे दी गई शुल्क तालिका से कॉलम 6 में दर्शाया गया है, पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाये जाने की सिफारिश करते हैं :

शुल्क तालिका

क्र. सं.	प्रशुल्क मद*	वस्तुओं का विवरण	मूल देश और/अथवा निर्यात	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2914 1100	एसिटोन	सिंगापुर	मित्सू फेनोल्स सिंगापुर पीटीई. लिमि.	56.91	अमरीकी डालर/ मी. ट.
2.			सिंगापुर	कोई भी	121.04	अमरीकी डालर/ मी. ट.
3.			यूरोपीय संघ	कोई भी	277.85	अमरीकी डालर/ मी. ट.
4.			दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	179.65	अमरीकी डालर/ मी. ट.
5.			संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	213.76	अमरीकी डालर/ मी. ट.

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जायेगा। ऊपर में उल्लेख किया गया विचाराधीन उत्पाद तब भी उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन होना चाहिए जब इसका आयात किसी अन्य एच एस कोड के अंतर्गत किया गया हो।

95. उपर्युक्त में सिफारिश किये गये अनुसार ये शुल्क दर उपर्युक्त कॉलम (5) में उल्लिखित निर्दिष्ट उत्पादक द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के लिए लागू हैं। सीमा शुल्क को संबद्ध वस्तुओं की निकासी के समय उत्पादक के नाम का सत्यापन करना चाहिए।
96. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य आकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया है और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाये गये शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का वर्तमान स्तर होगा।
97. आवेदक घरेलू उद्योग और उत्तर देने वाले उत्पादकों से यह अपेक्षित है कि वे संबद्ध वस्तुओं जिसके विरुद्ध पाटनरोधी उपायों की सिफारिश की जा रही है के लिए उक्त परिवर्तन की पुष्टि करते हुए संगत दस्तावेजों के साथ साथ निर्माण

सुविधा के गठन/स्वामित्व में किसी परिवर्तन के संबंध में प्राधिकारी को सूचित करना अपेक्षित है। यह पृष्ठना उक्त परिवर्तन, यदि कोई हो के 60 दिनों के भीतर प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

98. इस जांच परिणाम के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

(FINAL FINDING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2019

Case No. SSR 14/2018

Subject: Final finding in the second Sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of Acetone originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.

F. No. 7/26/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Anti-Dumping Rules or Rules), the Director General (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated 2nd sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of 'Acetone' (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America (hereinafter referred to as the subject countries).

A. BACKGROUND

- Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei, European Union, Singapore, South Africa and USA was initiated by the Authority on 7th September, 2006. The Authority, vide Preliminary Findings dated 25th April, 2007 recommended imposition of Provisional duty, which was imposed by Notification No. 77/2007-Customs dated 19th June, 2007. The Final Findings No. 14/4/2006-DGAD, dated 4th January, 2008, recommended imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei, European Union, Singapore, South Africa and USA, which was given effect to vide Notification No. 33/2008-Customs dated 11th March, 2008.
- Whereas, the Designated Authority conducted a midterm review investigation against imports of subject goods from Taiwan and recommended withdrawal of anti-dumping duty from subject goods originating in or exported from Taiwan vide Notification dated 10th April, 2012, which was given effect to vide Notification No. 29 /2012-Customs (ADD) dated 29th May, 2012.
- Whereas upon expiry of applicable duties at five years, the Authority initiated a sunset review and vide Final Finding Notification No. 15/1/2012-DGAD dated 13th December, 2013 recommended continuation of duty on import of the subject goods originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and USA. Accordingly, customs Authority issued a Notification No. 10/2014 Customs (ADD) dated 11th March 2014 for imposition of duty.
- Whereas in terms of Section 9A(5) the Act, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly

substantial request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. Whereas in terms of Section 9A(5) the Act, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. Whereas SI Group India Private Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd (hereinafter also referred to as the petitioners) along with support letter from M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), filed an application requesting initiation of sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed and seeking continuation of duties against imports from the European Union, Singapore, South Africa and United States of America. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.
7. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the 2nd sunset review investigation vide Notification No. 7/26/2018-DGAD dated 6th July, 2018 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

9. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation;
 - i. The Director General, under the Anti-Dumping Rules, received a written application from the petitioners on behalf of the domestic industry, requesting for continuation of anti-dumping duties against the imports of subject goods from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.
 - ii. On receipt of a duly substantiated application, the Authority issued Initiation Notification No. No. 7/26/2018-DGAD dated 6th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating second sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.
 - iii. The Embassy of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the sunset review investigations in accordance with Rule 6(2) along with the copy of the initiation notification and non-confidential version of the petition.
 - iv. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known producers / exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioners) and provided opportunity to make their views known in writing within 40 days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2) and Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.
 - a. Stonemill AB, Sweden
 - b. BOC Sciences, USA
 - c. EMCO Chemical Distributors Inc, USA
 - d. ICC Chemical Corporation, USA
 - e. BKM Resources Inc., USA
 - f. Miles Chemical Company Inc., USA
 - g. Hubbard-Hall, USA

- h. Ecolink, USA
- i. Seidler Chemical Co, Inc, USA
- j. ADD Resins and Chemicals (Pty) Ltd, South Africa
- k. Protea Chemicals, South Africa
- l. Sasol Solvents, South Africa
- m. Amka Products (Pty) Ltd. , South Africa
- n. Rolfes Holdings Limited, South Africa
- o. Yog Trading Pte. Ltd., Singapore
- p. Vigor Sphere Pte. Ltd. , Singapore
- q. Advance Pinnacle Technologies, Singapore
- r. Polymer Technologies Pte. Ltd. , Singapore
- s. Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd., Singapore
- v. There is no response from EU, South Africa and USA. The following producer and exporter from Singapore have filed a response to the exporter questionnaire
 - a. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 - b. Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.
- vi. The Authority forwarded copy of Notification to the following known importers/ consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):
 - a) M/s. C.J. Shah and Company
 - b) M/s. PCL Oil & Industries
 - c) M/s Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd
 - d) M/s Sonkamal Enterprises
 - e) M/s. Khetan Brothers
 - f) M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
 - g) M/s Acron Enterprises
 - h) M/s. Naiknavare Chemicals Limited
 - i) M/s. Paras Dyes & Chemicals
 - j) M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited,
 - k) M/s. United Phosphorus Ltd.
 - l) M/s. Resins & Plastic Ltd.
 - m) M/s. Kailash Polymers
 - n) M/s. Centrum Metalics Pvt. Ltd.
 - o) M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.
 - p) M/s. Meghdev Enterprises
 - q) M/s. Satguru International
 - r) M/s. High Polymer Labs Ltd.
 - s) M/s. Rainbow Colours & Chemicals
 - t) M/s. Haresh Kumar & Co.

- u) M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.
 - v) M/s. Karmen International (P) Ltd.
 - w) M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
 - x) M/s. NGP Industries Ltd.
 - y) M/s. Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd.
 - z) M/s. India Glycols Ltd.
 - aa) M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
 - bb) M/s. National Plywood Industries Ltd.
 - cc) Kundan Rice Mills Ltd.
- vii. Whereas none of the importers/ consumers responded to the importer questionnaire sent.
- viii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April 2017 to 31st March 2018 (12 months). However, injury analysis period covers 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.
- ix. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The Authority has, relied upon the DGCI&S data and the data of co-operative producer exporter for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods.
- xii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 18th September, 2018. The parties were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xiii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Finding.
- xiv. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding to the extent possible and verified the data / documents given by the domestic industry and producer exporter to the extent considered relevant and necessary.
- xv. A Disclosure Statement was issued on 22.02.2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 01.03.2019 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xvi. Information provided by the interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the

Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this Final Finding on the basis of the facts available.

xviii. *** in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xix. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1US\$= ₹ 65.33

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

Views of domestic industry

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- a. The product under consideration for the purpose of the present investigation is the same as in the earlier investigations, i.e., Acetone.
- b. The PUC is an organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used for manufacturing bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals.
- c. Since the present investigation is a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation, no significant developments have taken place over the period. Therefore the domestic industry refers to and relies upon the previous investigation with regard to product under consideration.

Views of the opposing interested parties

11. No submissions were made by the other interested parties with regard to the scope of product under consideration or like article.

Examination by the Authority

12. The product under consideration in the present sunset review investigation is Acetone. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone.

13. The present investigation being a sunset review investigation, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigations. The product under consideration defined in the previous investigations is as follows:

“6. The product under consideration is ‘Acetone’. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100.

7. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate.”

14. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the product being produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry is comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

15. The Authority holds that the product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration as mentioned in the paragraphs above, in accordance with the Anti-Dumping Rules. The subject goods produced by the petitioner companies are being treated by the Authority as like article to the subject goods imported from the subject countries, within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**Views of the domestic industry**

16. The domestic industry made the following submissions with regard to eligibility of the domestic industry and standing:
- i. The application was filed by M/s SI Group India Private Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd along with support from M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL).
 - ii. Deepak Phenolics has not imported the subject goods from the subject countries whereas SI Group has imported some quantity of the product under consideration which is only 1% of the total imports and 1% of the demand, from the subject countries. The petitioner imported the product under consideration under the advance license and is hence eligible to be considered as Domestic Industry.
 - iii. Petitioners are not related to any exporter or importer of the subject goods in the subject countries and importers in India either directly or indirectly.
 - iv. The Petitioners account for “a major proportion” of Indian production. Petitioners satisfy the requirement of standing to file the present petition and constitute “Domestic Industry” within the meaning of AD rules. This is without prejudice to the legal position that standing is not required to be examined at the stage of sunset reviews.
 - v. In compliance with the Initiation notification, the updated information for the period of investigation was filed by the petitioners considering HOCL as a part of the domestic industry.
 - vi. Petitioners have not claimed that Deepak Phenolics is an existing established Domestic Industry. Deepak Phenolics in part of the application only as a supporter.
 - vii. Deepak Phenolic is directly relevant for likelihood of injury having made a significant investment of Rs. 1400 Crores and will commence the commercial production of the subject goods catering to the significant demand in India.
 - viii. The applicants account for 100% of the domestic production. Therefore, the applicant companies constitute eligible domestic industry, as defined in Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

Views of the opposing interested parties

17. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to eligibility of the domestic industry and standing:
- a. Deepak Phenolics cannot be considered as DI, since they have not begun production during the POI.
 - b. SI Group has imported Acetone throughout, the reasons for the same have neither been disclosed nor have been analysed. Therefore, the imports made by SI Group under Advance License should be re-assessed by the Authority.
 - c. Deepak Phenolics has not started production yet; in fact the plant is yet to be commissioned. Hence the parameters as proposed by the Article 3 amendment are not applicable to Petitioners – (1) Capacity Utilization, (2) Delay is start of reasonable commercial production, (3) Domestic Production compared to domestic market.
 - d. HOCL is included in the determination as per the Designated Authority. However, it is not clear if HOCL is included in the scope of DI or not. Clarification on the same with reasoning is required.

Examination by the Authority

18. The petition has been filed by M/s SI Group India Private Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd alongwith support letter from M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL). Later, the Authority directed the petitioners to file relevant data for M/s HOCL. The relevant data was filed by the petitioners as directed.
19. It is noted that M/s Deepak Phenolics has not started the production yet and HOCL has not manufactured the product under consideration throughout the year. The SI group along with supporters accounts for 100% of the total Indian production. The petitioners have certified that they are not related to any exporter or importer in India.

20. SI group has imported small quantity of the PUC from the subject countries during the period of investigation. The imports were made under duty free authorization scheme. After examination it was noted that imports are in insignificant quantity as compared to total imports of the goods or the production of the goods by the producer.
21. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicants satisfy the standing requirements for the subject goods and constitute domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

Views of the domestic Industry

22. The domestic industry made the following submissions with regard to confidentiality
 - a. The responding exporters have resorted to excessive confidentiality claims which have completely prevented the Petitioners from offering their comments.
 - b. Injury statements filed by the domestic industry are invariably either on actual basis or on indexed basis. The comparison of the non-confidential version of the injury parameters by the domestic industry and by the responding exporters will clearly show the extend of excessive confidentiality claimed by the responding exporters.
 - c. The domestic industry has provided indexed figures of each parameters showing the trend of injury parameters, the exporters opted to provide range of the Indexed figures. The non-confidential version provided by the responding exporters is again an attempt to curtail the right of the petitioner to defend its interest.
 - d. The exporter has claimed information like product list, channel of distribution, production process, production flowchart, name of raw material, information regarding exports to India, sales of goods of the company, sales price structure, statement showing installed capacity, information related to cost of production, information related to subsidiary, information with regard to exports to third countries etc. Non-confidential version of the questionnaire response is grossly inadequate. The interested parties have not disclosed all such information that they are obliged to disclose under the Rules. Even information that is publicly available has not been disclosed in the non-confidential version
 - e. The petitioners have filed revised non confidential version of the information as per the recent Trade Notice No 10/2018 dated 7th September, 2018.

Views of the other interested parties

23. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
 - a. Evidence used for various costs to Construct Normal Value has been claimed as confidential. The claim is arbitrary in nature and directly hurts the interest of the Exporters.

Examination by the Authority

24. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**Views of the domestic industry**

25. The domestic industry made the following submissions:

- a. There are plethora of cases wherein the Designated Authority has included imports under advance license for examination of dumping and injury, while it is considering that these imports have occurred for export production. There is neither any legal nor any factual basis of exclusion of imports under advance license from determination of injury.
- b. Authority has in other cases also held that the fact that the imports were made under advance license does not mean that the same does not cause injury to the domestic industry.

Views of the opposing interested parties

26. The opposing interested parties have made the following submissions:

- a. As per market intelligence, a large portion of the imports have been made during the injury period as well as the POI under advance license scheme. Since the schemes are made to incentivize export oriented production and are exempted from levy of trade remedial levy, they should be excluded from the import volumes for injury analysis.
- b. Practice and Policies between different limbs of the Government should be consistent as per the Madras HC Judgment. Imports under Advance License are exempted from any anti-dumping duties to boost exports, whereas duties are being imposed now using the import volumes including such imports. According to CESTAT in Thai Acrylic Fibre v. DA, imports under Advance License do not enter Indian Market and compete with domestic sales.
- c. Imports under Advance License are beyond the scope of SSR. To examine if the cessation of duties will lead to continuation or recurrence of dumping and injury, examining imports that never affected by these duties is absurd. Only imports that were affected by the duty and were injuring the DI should be examined. Advance License imports will not be affected irrespective of the fact that there is a duty or not.

Examination by the Authority

27. The specific submissions made by the opposing parties and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

- a. The Authority notes that the law clearly envisages that the anti-dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority recommends anti-dumping duty only after following the requirements prescribed under the laws.
- b. The argument that imports made under advance license should be excluded from the total imports was examined. The Authority notes that imports/exports made under advance license cannot be considered to have not affected the domestic industry or the price in the domestic market. An Advance license/authorization holder has a choice either to import the inputs on a duty free basis or procure the same from indigenous sources by using the mechanism of Advance Release Order. The purpose of injury analysis is to examine and capture the effect of dumped imports on the domestic industry. Therefore, it would not be reasonable to exclude the duty free imports from the injury analysis. Further, import under advance license is a benchmark for the price at which goods can be imported by a consumer without payment of taxes and duties. It would not be appropriate to consider that imports made under advance license do not cause injury to the domestic industry. In fact exporters and importers should not worry if their claim is that imports take place only under duty free scheme because in that case imposition of duty will not impact them at all.

G. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

28. According to Section 9A (1) (c) of the Act, 'Normal Value' in relation to an article means:

“comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Views of the domestic industry

29. The domestic industry has made the following submissions with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin:

- a. There is no evidence publicly available with regard to actual transaction price of the producers. In view of this, the normal values for subject countries have been determined on the basis of estimates of cost of production
- b. To calculate the net export price, ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight should be adjusted.
- c. The dumping margin is not only positive, but also significant.
- d. There is continued dumping of the subject goods from the subject countries despite imposition of anti-dumping duties.
- e. Since the responding exporter/producer has not filed the necessary information within reasonable time, Authority is requested to reject the incomplete questionnaire response filed by the responding party and treat them as non-cooperating, in compliance with Rule 6(8) and Initiation notification.
- f. Neither the responding exporter/producer nor their representatives are new to these investigations and therefore they cannot claim that they were not aware of the existence of sunset review questionnaire Part 2. This is a clear case of intentional omission.

Views of the opposing interested parties

30. Authority should assess responses of exporters to determine if there has been a continuation of dumping at all.

Examination by Authority

31. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by the petitioner. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in the subject countries to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their normal value and export price. Responses were received only from the exporters of Singapore i.e. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. and Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.

I. NORMAL VALUE

SINGAPORE: M/s Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd. & M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.

32. The responding producer has submitted details of the sales of the subject goods in their home markets, the information so provided has been relied upon to determine the Normal value for the subject goods

after carrying out the ordinary course of trade test and sufficiency test. They have sold the goods directly and through their related company namely M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., The adjustments as claimed in respect of storage cost, bank charges, credit costs and other adjustments were accepted after verification to arrive at ex-factory normal value. The ex-factory cost was determined based on the books of accounts of the company and the same was compared with the ex-factory selling price of the goods sold in the domestic market. It was found that 100% sales are profitable. The Normal Value so determined is as mentioned in the dumping margin table below.

EU, SOUTH AFRICA AND USA.

33. The Authority notes that no other exporter/producer from other subject countries has responded to the exporter's questionnaire. Therefore, the Authority decides to construct the Normal Value for EU, S. Africa & USA based on best available facts in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the Normal Value of the product under consideration is to be determined based on constructed costs of production duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The constructed normal value is as mentioned in the dumping margin table below.

II. EXPORT PRICE

SINGAPORE: M/s Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd. & M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.

34. The M/s Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd. has produced and exported goods to India through their related exporter M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. They have furnished complete information relating to exports to India. The adjustments have been claimed on account of storage cost, Bank Charges and Credit Cost, the same were accepted after verification. The net export price so determined is as mentioned in the dumping margin table below.

EU, SOUTH AFRICA AND USA.

35. The Authority notes that none of the exporters from other subject countries have participated in the present case. In view thereof, the Authority decides to construct the net export price (with applicable adjustments) for all those exporters, who have not filed response, from DGCI&S import data.

H. DUMPING MARGIN

36. Considering the normal value and export price as above, the dumping margin for all exporters of the subject goods from the subject countries is proposed to be determined as below:

SN	Particulars	NV/CNV	NEP	Dumping Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. &	***	***	***	***	5 - 15
2	EU	***	612.03	***	***	35-45
3	South Africa	***	601.75	***	***	35-45
4	USA	***	671.59	***	***	35-45

37. It is seen that the dumping margin is positive and above *de-minimis* levels.

I. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the domestic industry

38. The domestic industry has submitted as follows with regard to injury and causal link:

- Demand for the PUC has increased during the injury period. It has increased by 17% in the Period of investigation since the base year.

- b. Imports from the subject countries have decreased in absolute terms during the injury period. The share of imports from subject countries constituted about 8% of total imports in India during the POI.
- c. Imports from other countries have increased, however the Domestic Industry has filed a separate petition with regards to the dumped imports of the PUC from third countries.
- d. There has been a significant price undercutting by the dumped imports from each of the subject countries.
- e. Prices of Domestic Industry are suffering from Price suppression as decline in selling price is more than decline in cost of production.
- f. Landed price of imports is much below the non-injurious price calculated because of which the domestic industry has been forced to sell at prices below the fair selling or non-injurious price despite existence of Anti-dumping duties.
- g. Production and capacity utilization decreased in 2015-16 and then increased in 2016-17 and the POI. The sales of the domestic industry decreased in till 2016-17, but increased in the POI.
- h. Despite the increase in Demand and market share of the Domestic Industry, the profitability has suffered and the Domestic Industry is in losses throughout the injury period.
- i. Inventories have increased over the injury period and are significant during the POI.
- j. The Domestic Industry has been suffering on profitability. The DI has remained in losses throughout the injury period, with the losses increasing in 2014-15 and 2016-17 with a minor improvement in the POI.
- k. The Return on Capital Employed has followed a similar trend while remaining negative throughout the injury period, with only a minor improvement coming in the POI.
- l. Imports from the third countries have increased. Petitioner has filed a separate petition for the same since the current investigation is a sunset review and new countries could not have been added.
- m. Demand for the product has increased and hence cannot be the cause for injury.
- n. Other known factors have been analysed are not the cause of injury to the Domestic Industry.
- o. The petitioners are claiming adverse price effect in the product under consideration and not adverse volume effects.
- p. Domestic Industry is forced to align its prices with the dumped imports to sell the PUC in the market.
- q. Since HOCL is a central government owned PSU, many macro-economic aspects of the company are managed by the government. Therefore, the macro economic issues that are being raised about HOCL cannot be treated as inefficiency on the part of working management of the company.
- r. Petitioners have submitted evidences which show HOCL has the lowest consumption factor and therefore is an efficient company as far as production of the product under consideration is concerned.
- s. The fact that import prices have not been aligned to raw material costs itself establishes the discriminatory pricing resorted by the foreign producers.

Views of the opposing parties

39. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury are as follows:

- a. Injury analysis is only to be done after assessment of standing of DI. Volume injury must consider imports made under Advance License.
- b. There is no volume injury as base year v. POI. Imports have significantly declined. The base year v. POI Imports in relation to production and demand/consumption have declined.
- c. Despite the alleged undercutting, the Petitioners are performing well.

- d. There is higher growth in profits in periods when there was higher undercutting. Thus, other factors are affecting the performance of the Petitioners and not the subject imports.
- e. Alleged undercutting has not affected the pricing of petitioners, since the costs have been aligned to the raw material pricing. Hence there is no suppression/depression.
- f. It has been admitted in the petition that economic parameters like production and sales volume have shown a positive trend. Hence, there is no injury on economic parameters.
- g. Even if continued dumping is established, there is no continued injury and hence causal link has broken.

Examination by Authority

40. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the other interested parties.
41. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
42. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
43. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries. For this purpose, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization and the magnitude and margin of dumping in accordance with Annexure – II of the Rules.

III. ASSESSMENT OF DEMAND

44. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales and captive consumption of the applicant and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Sales of domestic industry	MT	19,937	22,401	21,620	22,341
2	Sales of Supporter	MT	6,167	2,648	4,722	10,609
3	Imports from subject countries	MT	20,701	24,080	10,167	14,539
4	Imports from Countries attracting duty	MT	104,082	94,173	56,869	42,257
5	Imports from other countries	MT	1,989	20,096	68,801	89,811
6	Total demand	MT	152,876	163,399	162,180	179,556
6a	Trend	Indexed	100	107	106	117

45. It is noted that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period including POI except for the year 2016-17.

IV. VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

i. Import volumes and market share of imports

46. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S.

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Imports from subject countries	MT	20,701	24,080	10,167	14,539
2	Imports from Countries attracting duty	MT	104,082	94,173	56,869	42,257
3	Imports from other countries	MT	1,989	20,096	68,801	89,811
4	Total imports	MT	126,772	138,350	135,838	146,606
Subject Countries Imports in relation to						
5	Indian production	%	79.67	96.48	38.09	44.23
6	Demand	%	13.54	14.74	6.27	8.10

47. It is seen that:

- The Imports from the subject countries have decreased in the POI as compared to base year but have increased in POI in comparison to the previous year.
- Imports from subject countries in relation to Indian production increased in 2015-16, thereafter declined.
- Imports in relation to total demand have shown the same trend as the imports in relation to production.

V. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS

48. With regard to the effect of the dumped imports on prices, lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub rule (2) of rule 18 the Director General shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a, significant degree."

49. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Director General is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

50. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the domestic industry has given information for comparison between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The DI further stated that price of bulk and drum packing is different and have given details for both separately. Accordingly, the domestic prices and margin of undercutting for all four subject countries is shown as per the table below:

EU

SN	Particulars	Unit	POI	Bulk	Packed
1	Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	***	***	***
2	Landed Value of imports	Rs/MT	50,956	50,917	53,579
3	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
3a	Price undercutting	%	***	***	***
3b	Price undercutting	Range	5-15	5-15	10-20

Singapore

SN	Particulars	Unit	POI	Bulk	Packed
1	Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	***	***	***
2	Landed Value of imports	Rs/MT	50,803	50,765	64,640
3	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
3a	Price undercutting	%	***	***	***
3b	Price undercutting	Range	5-15	5-15	0-10

South Africa

SN	Particulars	Unit	POI	Bulk	Packed
1	Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	***	***	***
2	Landed Value of imports	Rs/MT	51,612	49,589	67,859
3	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
3a	Price undercutting	%	***	***	***
3b	Price undercutting		5-15	5-15	(negative)

USA

SN	Particulars	Unit	POI	Bulk	Packed
1	Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	-	-	***
2	Landed Value of imports	Rs/MT	-	-	56,864
3	Price undercutting	Rs/MT	-	-	***
3a	Price undercutting	%	-	-	***
3b	Price undercutting	Range	-	-	10-20

51. It is seen that the price undercutting, taken as a whole for the differently packed goods, is positive from European Union, Singapore and South Africa in the period of investigation whereas it is negative for

United States. As regards United States, there are imports of only packed acetone from United States which are undercutting the prices of the domestic industry.

ii. Price Suppression and Depression

52. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the domestic industry has given information for the changes in the costs and prices over the injury period as below:

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Landed price of Imports -EU	Rs/MT	73,459	44,936	88,144	50,956
1a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	120	69
2	Landed price of Imports - Singapore	Rs/MT	66,331	36,814	44,881	50,803
2a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	56	68	77
3	Landed price of Imports -South Africa	Rs/MT	80,507	53,452	50,997	51,612
3a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	66	63	64
4	Landed price of Imports -USA	Rs/MT	51,450	-	-	56,864
4a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	-	-	111
5	Landed price of Imports - Subject countries	Rs/MT	69,829	42,327	45,065	50,904
5a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	65	73
6	Cost of sales of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
6a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	65	69	76
7	Selling price of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
7a	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	63	74	76

53. It is seen that the landed value has declined in POI as compared to base year. The Cost of sales and selling price has also declined during the injury period as compared to base year. But the landed value of imports is below the cost price and selling price of the Domestic Industry throughout the injury period including POI (except for base year when Landed Value was higher than the cost and selling price). Further, it is noted that selling price is lower than cost of sales which is due to presence of low prices imports in the market. Therefore, it is seen that the imports are having a suppressing and depressing effect on the domestic prices.

iii. Price Underselling

54. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling.

SN	Particulars	UOM	EU	Singapore	South Africa	USA
1	Import Volume	MT	6,996	7,184	338	20
2	Landed value of Imports	Rs/MT	50,956	50,803	51,612	56,864
3	Non-Injurious Price*	Rs/MT	***	***	***	***

SN	Particulars	UOM	EU	Singapore	South Africa	USA
4	Price Underselling	Rs/MT	***	***	***	***
4a	Price Underselling	%	***	***	***	***
4b	Price Underselling	Range	5-15	5-15	5-15	5-15

(*Countrywise NIP has been determined separately bulk and packed goods and weighted average is taken on the basis of imports quantity)

55. From a comparison of the landed value (without adding anti-dumping duties) with the non-injurious price, it is noted that the price underselling is positive.

VI. ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY

56. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of alleged imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes

57. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Capacity	MT	22,500	22,500	22,500	22,500
2	Production	MT	19,816	22,311	21,974	22,263
3	Capacity Utilization	%	88.07	99.16	97.66	98.95
4	Domestic Sales	MT	19,937	22,401	21,620	22,341

58. It is seen that the capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period. The production, capacity utilization and sales of the domestic industry has increased during the POI when compared to base year.

ii. Market Share in Demand

59. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Subject Countries' imports	%	13.54	14.74	6.27	8.10
2	Countries Already Attracting Duty	%	68.08	57.63	35.07	23.53
3	Other Countries	%	1.30	12.30	42.42	50.02
4	DI Domestic Sales	%	13.04	13.71	13.33	12.44
5	Supporters	%	4.03	1.62	2.91	5.91
6	Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

60. It is seen that the market share of the subject countries have declined throughout the injury period whereas, market share of the domestic sales have also declined. The market share of other countries has increased. It has been the claim of the petitioner that dumped imports keep shifting from country to country as and when the duties are imposed and they cease to exist.

iii. Inventories

61. The data relating to inventory of the subject goods as shown in the following table indicates an increasing trend:

UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
MT	***	***	***	***
Trend	100	57	110	167

iv. Profit or Loss, Cash Profits and Return on Investment

62. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry is as follows:

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Profit/(Loss) - Domestic	▪ / MT	***	***	***	***
1a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(159)</i>	<i>146</i>	<i>(42)</i>
2	Profit/(Loss) – Domestic	▪ Lacs	***	***	***	***
2a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(141)</i>	<i>135</i>	<i>(38)</i>
3	Cash Profit	▪ Lacs	***	***	***	***
3a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(172)</i>	<i>194</i>	<i>(25)</i>
4	Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
4a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>(100)</i>	<i>(200)</i>	<i>263</i>	<i>(84)</i>

63. It is noted that the domestic industry is suffering losses throughout the injury period except 2016-17. The domestic industry has claimed that these losses are due to continuous presence of dumped imports. The losses to the domestic industry have declined during period of investigation as compared to base year. The company is faced with cash losses and negative return on investments during POI.

v. Employment, Wages and Productivity

64. The employment and wages are below:

SN	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Wages per Unit	▪ / MT	***	***	***	***
1a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>88</i>	<i>93</i>
2	No of Employees	Nos	***	***	***	***
2a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>110</i>	<i>113</i>
3	Productivity /Employee	MT	***	***	***	***
3a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>101</i>	<i>99</i>
4	Productivity /day	MT	57	64	63	64
4a	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>111</i>	<i>112</i>

65. It is seen that the number of employees has increased over the injury period. The wages per unit has declined over the injury period. Productivity per employee has declined marginally in the period of investigation whereas productivity per day has increased in the period of investigation.

vi. Magnitude of Dumping

66. It is noted that the dumping margin is positive and above de-minimis.

vii. Injury Margin

67. The Injury margin has been calculated for the cooperative responding producer exporter from Singapore by comparing the non-injurious price with the landed value of the subject goods as verified and for others from import data.

SN	Particulars	LV	NIP	Injury Margin		
		Rs /MT	Rs/MT	Rs /MT	%	Range
1	Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	***	***	***	***	5 - 15
2	EU	50,956	***	***	***	5 - 15
3	South Africa	51,612	***	***	***	5 - 15
4	USA	56,864	***	***	***	5 - 15

(*Countrywise NIP has been determined based on weighted avg of imports in bulk and packed)

J. CONCLUSION ON INJURY

68. It is thus seen that the Imports from the subject countries have decreased in the POI as compared to base year but have increased in POI in comparison to the previous year. Imports have increased significantly in post POI period. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have had an adverse price effect in terms of price depression and price suppression. The domestic industry is also suffering significant price underselling. The dumping margins determined are significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of profits, cash profits and return on investment. The inventories with the domestic have also increased. The Authority concludes that the domestic industry has suffered continued injury.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION / RECURRENCE OF DUMPING & INJURY

Views of the domestic industry

69. The submissions made by the Domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:
- Producers in subject countries maintain huge capacities to produce subject goods.
 - Producers in subject countries are having freely disposable production capacities.
 - The exporters from subject countries have very high export orientation worldwide as can be clearly seen from the increase in total exports.
 - The landed price of imports is below the cost and selling price of the domestic industry, hence the imports are likely to suppress the prices of domestic industry.
 - Despite existing anti-dumping duty, the exporters from China have continued exports to India at dumped prices. Thus, it is very likely that in the absence of such a duty, the dumping of the subject goods in India will continue.
 - Dumping margin from each of the subject countries is positive and above de minimus levels. The subject countries have continued to export the product under consideration at dumped prices

throughout the injury period. In the event of cessation of anti-dumping duty, the imports in all likelihood will continue at dumped prices causing injury to the domestic industry.

- g. Designated Authority has by now decided a number of midterm and sunset review investigations. Determination of injury in midterm and sunset review is the same or similar. The Designated Authority has in the past recommended extension of anti-dumping duties in similarly placed situations. Further, a number of decisions of the Hon'ble Tribunal are directly applicable in the facts & circumstances of the present case.
- h. There are number of countries in the world that have extended anti dumping duties even beyond 20-20 years. The domestic industry has placed on record the list of such cases and countries that have extended duties beyond 20-30 years.
- i. India is attracting anti-dumping duties on its exports of jute bags to Brazil since 1992. Though there is no known export of jute bags to Brazil, yet these duties have been extended in successive sunset reviews in this case.
- j. Despite the anti-dumping duties in force, the domestic industry has not been able to earn a reasonable return on the capital employed. Any further decline in profitability will hit the domestic industry hard.
- k. It is evident that if the duty was to be ceased, the imports are likely to enter the market at dumped prices. Thereafter, the domestic industry would not be in a position to maintain its market share, unless it is willing to sell at less than profitable prices and vice versa.
- l. The total profits of the domestic industry would fall and its return on investment would reduce further. Therefore, it can be concluded that the subject imports are likely to cause injury to the domestic industry in the event of cessation of duty.
- m. Trade Notice No. 02/2017 does not mention filing of post POI data as a mandatory criterion for filing sunset review, failing which the investigation would be terminated. Regardless, the Post POI data is not required in the current case to establish merits.
- n. All evidences have been provided for the likelihood parameters such as excess capacity, freely disposable capacities and export orientation.
- o. Domestic Industry is suffering injury. Likelihood is also to be considered in case a determination is made that the domestic industry is not suffering from injury.
- p. Freely disposable capacity is calculated as the capacity which is unutilized by the exporters, which capacity minus capacity and evidences have been provided for the same. Producers/Exporters were not able to refute the same with any evidence.
- q. Mitsui group has not filed response to part 2 of the exporter questionnaire response, which seeks information from the exporter on their capacities, capacity expansion, transaction wise third countries exports, domestic sales, inventories etc. which is indicative of their likelihood behaviour.
- r. Global exports to China are decreasing gradually due to the recent capacity expansions carried out in China. Due to the self-sufficiency, China has removed the need for imports and therefore, India remains to be a highly lucrative market.

Views of the opposing parties

70. The submissions of the other interested parties, with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are summarized hereunder:

- a. Post-POI data has not been provided; hence likelihood determination is not possible. DA is requested to reject data and terminate the investigation.
- b. Petitioners have tried to shift Burden of Proof on the exporters to establish no likelihood, whereas the averment has no legal basis.
- c. No post POI data has been provided; hence it cannot be assessed if subject goods are being currently dumped or not.

- d. No evidences have been provided for alleged large capacities in subject countries. If there is any, the capacities in Singapore are getting absorbed by third countries. Also, since there is no capacity expansion in the countries, there is no likelihood involved.
- e. Freely disposable capacity is calculated by a mere subtraction of demand in subject countries from alleged capacities. Hence, the calculation is not validated.
- f. There is no evidence at all for alleged high export orientation of the exporters.
- g. Singapore export prices to third countries are comparable with Indian prices even after addition of ADD. Should there be attractiveness, there would have been an increase in volume of imports. Duties have no effect, since the price difference is not significant.
- h. No post-POI data with respect to inventory levels in the Subject Countries has been provided, nor is there any other evidence for the same.
- i. China is a net-importer of the subject goods, with a similar pricing as India and hence is much more attractive destination for the Exporters.

Examination by Authority

71. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duty, in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides, inter alia for four factors which are required to be taken into consideration, viz.:
 - a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article being investigated.

Further, the Authority has also examined any other relevant factor having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

72. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

i. Post POI imports

73. For examining the Post POI period imports into India, we have obtained data from DGCI&S and from that it can be seen that imports during Post POI have further increased when compared to POI.

SN	Import Volume	UOM	POI	Post POI (Apr'18-Dec'18)	Post POI annualised
1	Subject countries	MT	14,539	30,098	40,131
2	EU	MT	6,996	6,169	8,225
3	Singapore	MT	7,184	15,638	20,851
4	South Africa	MT	338	666	888
5	USA	MT	20	7,625	10,167

74. Further it is noted that the prices from subject countries in post POI has declined as compared to POI despite increase in raw material prices. In the event of cessation of anti-dumping duties, the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices.

ii. Excess Surplus Production Capacities

75. The Domestic Industry has given information regarding Excessive production capacities in subject countries:

Sr. No	Exporter	Countries	Capacity in MT
1	INEOS	Germany	415000
2	INEOS	Belgium	395000
3	Borealis	EU	120000
4	Versalis	EU	185000
5	Novapex	EU	108000
6	CESPA	EU	370000
7	Others	EU	158000
9	Shell	USA	360000
10	INEOS	USA	330000
11	Honeywell	USA	310000
12	DOW	USA	180000
13	SABIC	USA	208000
14	Haverhill	USA	173000
15	Axiall	USA	140000
16	DOW	USA	77000
19	Mitsui Phenol	Singapore	180000
20	Sasol solvents	South Africa	175000
21	Others		36740
22	Total		3920740

Source: ICIS reports

76. Summarized position can be seen as below –

SN	Particulars	EU	USA	Singapore	South Africa	Total
1	Capacities	18,41,000	18,14,740	1,80,000	1,75,000	40,10,740
2	Demand	17,00,000	14,00,000	2854	65,200	31,65,200
3	Surplus	1,41,000	4,14,740	1,77,146	1,09,800	8,45,540

77. Domestic industry has stated that the huge production capacities in the subject countries in excess of the demand in their respective market indicates the likelihood of diversion of surplus quantities.
78. The exporters have stated that “Excess capacity” in a country per se does not mean likelihood of dumping. The production in the subject countries as on date is already tied to demands in different countries. The produced quantities is not lying idle that it would be immediately diverted to India as apprehended by the domestic industry.

79. It is however noted that the exporters have not provided any information in the prescribed format to show that the capacities with the exporters are already tied up to the demands in different countries. In fact, it is seen that there is significant increase in imports from Singapore in the post POI (imports were almost three times the levels of POI). Further, the information provided by the petitioner on the basis of customs data shows that the weighted average export price from Singapore to third countries is lower than export price to India and there are significant exports to a number of countries at prices below export price to India. On the basis of evidence on record, it is noted that there exist excess production capacities in the subject countries and there is a possibility of diversion of the excess quantities to Indian market, in the event of cessation of anti-dumping duties.

iii. High export orientation of the foreign producers

80. The domestic Industry has furnished details of exports made by the subject countries during investigation period as given below:

SN	Subject countries	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	EU	MT	692,778	708,625	705,406	826,805
2	USA	MT	162,863	173,173	124,501	117,989
3	Singapore	MT	165,764	138,242	170,237	127,887
4	South Africa	MT	69,376	74,645	75,038	73,327
5	Total	MT	1,090,782	1,094,686	1,075,182	1,146,008

81. It is noted that the exports by the subject countries have been increasing over the years, indicating their high export orientation. The exporter from Singapore have contested that high export orientation worldwide is not indicative of any likelihood of increased dumping into India. It is however noted that exports to third countries are at a price lower than exports to India, imports from Singapore in post POI are almost three times the imports in POI and there are significant exports to a number of countries at a price lower than export price to India.

iv. Attractiveness of India as a market

SN	Particulars	UOM	EU	USA	Singapore	South Africa
1	Landed Value of imports	₹ /MT	50,956	56,864	50,803	51,612
2	Net selling price of Domestic Industry	₹ /MT	***	***	***	***
3	Cost of sales of the domestic industry	₹ /MT	***	***	***	***

82. It can be seen that the Landed value of imports is below the Cost of sales & the Net selling price of the Domestic Industry. The exporters have strongly contested the price attractive of Indian market as the prices at which subject goods are exported to third countries are comparable to India. The Authority has further examined the price of exports from subject countries to third countries, and it is found that the exporters of subject countries are exporting the product under consideration to a number of countries at prices lower than Indian prices, thereby clearly showing price attractiveness of Indian market. In the event of cessation of anti-dumping, the exporters in subject countries are likely to export the product in India at dumped pricing causing injury to the domestic industry.

Conclusion on Likelihood

83. In view of the above facts and evidence on record, it is noted that there is a likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duties.

L. CAUSAL LINK**Views of domestic industry**

84. The submissions of the domestic industries, with regard to causal link are summarized hereunder:

- a. Price Undercutting is positive from all the countries, infact the landed price is even below the cost of sales.
- b. The prices of the Domestic Industry are being suppressed by the dumped imports.
- c. Domestic Industry is forced to align its prices to that of imports, and is consequently suffering heavy price injury.
- d. Dumping has continued despite existence of Anti-dumping duties.
- e. The period for which duty has been in force is no relevant consideration to determine whether antidumping duty is required to be extended further.
- f. The GOI has approved a restructuring plan for HOCL, which will carry out a structured closure of non-viable units and will raise revenue for the effective plant of Acetone. During the 1st quarter of 2018-19, the plant was running at 98% capacity utilization.
- g. The Petitioners have filed a separate petition for anti-dumping investigation against dumped imports from other countries. However, since the landed price of the subject countries without ADD is very much comparable to the landed price from other countries shows that there is a huge likelihood of injury from the subject countries on cessation of ADD.
- h. Sickness of HOCL was due to the underperforming Rasayani plant. Under the new restructuring planned passed by the GOI, the Rasayani plant will be sold with proceeds from the sale going to the PUC producing Kochi plant.
- i. Separate statements showing profits of Kochi and Rasayani plants have been submitted. It established that the Kochi plant is efficient.

Views of the opposing parties

85. The submissions of the other interested parties, with regard to causal link are summarized hereunder:

- a. Period of duty is irrelevant, as asserted in the petition and the petitioners will perform at sub-optimal levels no matter how long the duty goes.
- b. HOCL injury is self-inflicted in nature and due to their own inefficiencies.
- c. Price of imports from Japan and Thailand is similar to other countries. After expiry of duty, imports from Thailand count for 42% of total imports and the prices are in line with other countries. Hence, the effect of continuation of duties is not significant.
- d. HOCL is operating with a buffer of ADD to soften its inefficiency for over 10 years. Exaggerated plans to expand and reduce costs were provided during Safeguards investigation, but the capacity has been the same since 1999. This shows inability to overcome its infectivity.
- e. Scrutiny is required of HOCL's prolonged poor performance. Despite comfort of ADD, they have been termed as Sick Company till 2015-16.
- f. There is huge demand supply gap in the country during the POI and this is main reason for the imports.

Examination by Authority

86. The examination reveals that there is positive significant dumping margin and injury margin during the POI. The likelihood analysis also clearly points to the situation that dumping and consequent injury to the DI will intensify in case Anti dumping duty ceases to exist. The concern regarding demand and supply gap is likely to be addressed by entry of other Indian producer, who is supporting this petition. Moreover, this cannot be the reason for exporting countries to enter into unfair trade practices like dumping.

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

87. The post disclosure submissions have been received from the domestic industry and the exporter from Singapore. No other foreign producer/exporter or other interested party has filed any comments. The issues raised by these interested parties are largely repetitive. The issues raised therein had been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

Views of the domestic industry

88. Submissions made by the domestic industry post issuance of disclosure statement are summarized as under:

- a. Disclosure statement does not constitute sufficient disclosure of essential facts. It is silent on the likelihood of continuation of dumping. Domestic Industry has made submissions with regards to likelihood based on actual facts and evidences. The same has not been considered in the Disclosure.
- b. Vital arguments raised by domestic industry with detailed submissions, that have not been considered in the Disclosure Statement, for example (1) non filing of Part 2 of the sunset review questionnaire by Mitsui (2) excessive confidentiality claimed by the exporters (3) submissions on likelihood of dumping and injury.
- c. The Authority has not treated HOCL as the domestic industry. The fact that HOCL has intermittently not manufactured the product under consideration cannot be a ground for excluding HOCL as domestic industry.
- d. The responding producer has exported the PUC through related entity. Therefore, export price is required to be adjusted for SGA & Profit of related trader. The export price determined is over stated. The exporter has reported no adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, inland insurance, port and handling charges etc.
- e. Since the Singapore producer has supplied both bulk and packed material, it is not clear whether the normal value and export price have been separately compared for bulk and packed product. If not so, treatment of difference in cost and price of packed and bulk material becomes important.
- f. As per WTO report, there is no requirement of causal link in a sunset review investigation. Notwithstanding there exist a causal link between dumping and injury in the present investigation.
- g. The petitioner understands that normation has been done for Cumene for determination of NIP. If so, this is clearly beyond Annexure III provisions which require consideration of the cost of production of the captive input and not normated cost of production.
- h. The disclosure of NIP shows that the Authority has infact applied suppressing effect of prices in period of investigation rather than merely limiting to inefficiencies in raw material consumption. This has led to lower NIP to suppressed prices. Authority is requested to kindly revise the NIP calculation and consequently the injury margin.
- i. The Authority is requested to extend the same duty in US\$ terms.

Views of the other interested parties

89. Submissions made by the domestic industry post issuance of disclosure statement are summarized below:

- a. The disclosure statement is not clear about the composition of domestic industry as the composition of domestic industry kept changing throughout the investigation period. The data relied on by the Authority in the disclosure statement matches the data of the first petition filed by the petitioner which was filed by SI Group, Deepak Phenolic.
- b. The exporters believes from the disclosure statement that the Authority has considered SI Group, Deepak Phenolic and HOCL as domestic industry and the exporters objects to that because a non producing member can not be considered as the member of domestic industry. Deepak Phenolics has not begun its production hence cannot be considered as domestic industry.

- c. There is increase in demand but imports from the subject countries have decreased in the POI and the sales of the domestic industry have increased, hence there is no impact of imports from the subject countries on the domestic industry as well as the supporter HOCL.
- d. The price undercutting is positive for Singapore for packed as well as bulk. The Authority has not given price undercutting for the previous year.
- e. The domestic industry has been able to change their prices in line with the cost of sales. Landed price from Singapore is more than the cost of sales of the domestic industry. Hence, there is no suppression or depression.
- f. There is no material injury to the domestic industry and the annual report of SI Group and HOCL suggest the same.
- g. Post POI data has not been provided to the interested parties and has been used in the disclosure statement as and when suited to the domestic industry. No data is made available on whether this import is on dumped prices and it is also not clear how the ROCE, profitability and other key performance parameters look during the post POI.
- h. Even if there is continued dumping there is absence of continued or recurrence of injury. There is absence of causal link between the imports and the performance of the domestic industry. If at all there is an injury that is on account of HOCL.
- i. Freely disposable capacities to be examined after taking into account the availability of other exports market to absorb any additional exports. Domestic industry has not provided any evidence if the other markets have the ability to absorb the additional exports.
- j. Data shows that Singapore's prices to third countries are comparable to prices in India. Prices to India and China are comparable. In fact China is more of an attractive market for Singapore because of the quantity of exports.
- k. Any new fact considered by the Authority while analyzing causal link should be known to the exporters because the Authority has not disclosed various facts in the disclosure statement with regard to HOCL and its performance. Causal link is an important factor for analyzing whether to continue or rescind the duty in force.
- l. The Authority should also examine if injury to the domestic industry is due to SI groups imports from the non subject countries.

Examination by Authority

90. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the interested parties are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and properly addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The authority further considers as follows with regard to issues raised by the interested parties:
- a. It is noted that only one producer from Singapore has responded to the Authority. None of the producers from other subject countries have cooperated with the Authority. The responding producer & exporter from Singapore has not provided prescribed information with regard to its exports to various third countries.
 - b. As regards composition of domestic industry, the disclosure statement clearly stated the composition and it is further clarified that that the application was filed by M/s SI Group India Private Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd along with support letter from M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL). Since M/s Deepak Phenolics had not started the production during POI and HOCL has not continuously produced during POI, only SI group has been considered as a domestic industry for the purpose of present investigation. There is no confusion in the disclosure statement with regard to composition of domestic industry.
 - c. As regards difference in the data between petition and disclosure statement, while the exporter itself has stated that there is no difference in the data if SI Group is considered. In any case, the Authority has considered verified data for the present purposes.

- d. In relation to facts pertaining to likelihood of dumping and injury submitted by the interested parties, it is noted that the same has been examined appropriately, in the relevant paragraphs recorded in the final findings.
- e. As regards the submission made by the interested parties that the Authority has not disclosed all essential facts, it is noted that the disclosure statement issued by the Authority contained all essential facts in terms of Rule 16.
- f. As regards argument of the domestic industry with regard to NIP calculations, relevant calculations have been provided to the petitioner which are on the basis of information and records provided by the petitioner. The Company had furnished audited Cost Audit Report for the year 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18. As per the Cost Audit Report the company is consistently declaring Cost of Production and Cost of Sales of Cumene, Phenol, Acetone etc to Ministry of Corporate Affairs as per the statutory requirements. Cumene is a finished product and the company is selling it in the open Market. Cumene is manufactured from Benzene and Propylene and is also captively used for manufacture of Phenol and Acetone. For the determination of NIP, Cumene consumption to produce Acetone is taken from the audited cost audit report of the company. Normation of Cumene is done as per Annexure III. In view of the same, NIP determined by the Authority is appropriate.
- g. As regards the export price calculation for the cooperating producer and exporter from Singapore, the Authority has determined the export price based on the information filed and verified. The expenses borne by the exporter (including shipping expenses, commission, bank charges and credit cost) were duly reported, verified and duly adjusted for relevant SG&A expenses & profit margin of the exporter and post-factory expenses reported by the producer. In view of the same, ex-factory price determined by the Authority is appropriate.
- h. As regards computation for bulk and packed sales separately, it has already been clarified in the disclosure statement that the Authority has determined the margin for dumping and injury separately for bulk and packed sales, and appropriate adjustments have been made to enable the comparison wherever necessary.
- i. As regards decline in imports, it is noted that the volume of imports has significantly increased in post-POI period. The domestic industry even contended that the dumping margin and injury margin in post POI has increased further.
- j. As regards price undercutting over the injury period, it is noted that the price undercutting is required to be determined only for the investigation period.
- k. As regards absence of suppression/depression, as noted hereinabove, the prices of the domestic industry in the POI were clearly suppressed, leading to a situation where the domestic industry once again started suffering financial losses from a situation of profits in preceding year.
- l. As regards non disclosure of price underselling separately for different forms, the Authority considers that it is not necessary to show these separately for different forms in the disclosure statement. The Authority has done separate comparison and weighted average of the same has been appropriately reflected in the disclosure statement and these findings.
- m. As regards disclosure of post POI data, the Authority has considered publicly available data with regard to imports in post POI. Further, these have been appropriately disclosed in the disclosure statement itself.
- n. As regards consideration of freely disposable capacities after taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports, the Authority notes that the exporter has not established absence of freely disposable capacities after showing firm commitments in third countries. In fact, the data shows significant increase in imports from Singapore and subject countries as a whole, which clearly shows absence of any firm commitments in third countries market.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

91. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage

gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

O. CONCLUSION

92. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

- a. The product under consideration continues to be imported at the dumped prices from the subject countries;
- b. The domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports;
- c. The continued injury to the domestic industry is on account of dumped imports and is likely to continue if the anti dumping duties from subject countries are ceased;
- d. The information on record clearly shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the ADD in force is allowed to cease at this stage;
- e. One producer exporter has cooperated from Singapore during the review investigation. M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd has exported to India below the normal value and dumped imports are causing the material injury to the DI;
- f. None of the producers exporters from European Union, South Africa and United States of America have co-operated in the present review investigation. The data available indicates that exports from these countries have been made at prices below the normal value.

P. RECOMMENDATIONS

93. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal links, likelihood of dumping and injury, if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required against all the subject countries.
94. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry in case of the co-operative responding producer exporter from Singapore and extend the earlier duty in respect of all other non responding entities. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America, as indicated in Col 6 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government:

DUTY TABLE

Sr. No	Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin and/or Export	Producer	Duty Amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2914 1100	Acetone	Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd	56.91	USD/MT
2.			Singapore	Any other	121.04	USD/MT

3.			European Union	Any	277.85	USD/MT
4.			South Africa	Any	179.65	USD/MT
5.			USA	Any	213.76	USD/MT

* Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

95. The duty rates as recommended above are applicable for exports of subject goods manufactured by specified producer mentioned in column (5) above. The Customs should verify the name of the producer at the time of clearance of subject goods.
96. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
97. The applicant domestic industry and the responding producers are required to inform the Authority regarding any change in constitution/ ownership of the manufacturing facility, along with relevant documents substantiating the said change, for the subject goods against which Anti-Dumping Measures are being recommended. The information should reach the Authority within 60 days of the said change, if any.
98. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General